रायपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, नरसिंहपुर, सिवनी से एक साथ प्रकाशित

yashbharat.co.in

नये जमाने के साथ..

यश भारत

● वर्ष-1 अंक-171 ● रायपुर ● शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2026 ● मूल्य- 4 रुपए ● पृष्ठ-8 ● कार्तिक शुक्ल पक्ष 4 ● विक्रम संवत् 2083

हार मान लेना कमजोरी है, और आगे बढ़ना ताकत की निशानी है।

ISIS से जुड़े विद्रोहियों का खूनी हमला, कांगो में की 22 लोगों की हत्या; 10 से ज्यादा का अपहरण

इतुरी, एजेंसी। कांगो के पूर्वी हिस्से में इस्लामिक स्टेट यानी कि ह्वस्ह्वर से जुड़े विद्रोहियों ने एक बार फिर खूनी हमले किए हैं। पिछले 2 दिनों में विद्रोहियों ने युगांडा की सीमा के पास स्थित कई दूरदराज के गांवों को निशाना बनाया। नागरिक संगठनों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन हमलों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया गया। हमलों के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले एक और अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भी कत्लेआम हुआ था और 62 लोगों की हत्या कर दी गई थी।नागरिक संगठनों और मानवाधिकारों पर नजर रखने वाले दो समूहों के मुताबिक, ये हमले कांगो के पूर्वी इतुरी प्रांत के मंबासा इलाके में 8 अलग-अलग स्थानों पर किए गए। हमलों को अंजाम देने वाले विद्रोही संगठन का नाम एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज या, एडीएफ है। यह संगठन लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय है और आम नागरिकों को निशाना बनाता रहा है।

50 हजार की रिश्वत लेते डाक अधीक्षक गिरफ्तार, सहयोगी क्लर्क भी पकड़ा

मोतिहारी, एजेंसी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंपारण प्रमंडल के डाक अधीक्षक संजीव शरण सुमन को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में उनके सहयोगी क्लर्क अभिषेक को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना से पहुंची सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद टीम अपने साथ पटना ले गई। कार्रवाई की खबर फैलते ही डाक विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, मलाही डाकघर में पदस्थ कर्मचारी राहुल झा ने डाक अधीक्षक के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की थी। शिकायत में रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद पटना से सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम मोतिहारी पहुंची और मामले की जांच के बाद कार्रवाई की तैयारी की।

महाराष्ट्र तीन समुद्र तटों को मिला अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सम्मान

मुंबई, यशभारत। महाराष्ट्र पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य के तीन समुद्र तटों को पहली बार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। इनमें रत्नागिरी जिले के लाडघर और गुहागर तथा रायगढ़ जिले का श्रीवर्धन समुद्र तट शामिल हैं। वर्ष 2026-27 के लिए मिली इस मान्यता से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर महाराष्ट्र की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है।अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जूरी ने निर्धारित गुणवत्ता मानकों के आधार पर इन समुद्र तटों का चयन किया है। इसके लिए समुद्र तटों की स्वच्छता, पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यटकों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और सतत पर्यटन प्रबंधन जैसे मानकों को आधार बनाया गया। इस उपलब्धि के पीछे राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और बीच मैनेजमेंट कमेटियों के संयुक्त प्रयास रहे हैं।

महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर आज ईडी कोर्ट में होगा पेश, रिमांड पर लेने की तैयारी

रायपुर, यशभारत। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को शुक्रवार को प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर जेल से ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत में आवेदन खारिज होने के बाद ईडी ने रायपुर की विशेष अदालत में उसे पेश करने के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब ईडी सौरभ को कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच एजेंसी का मानना है कि सौरभ से पूछताछ में ऑनलाइन सट्टे के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, हवाला के जरिए हुए करोड़ों के लेन-देन और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

दरअसल, आठ दिन की सीबीआई रिमांड समाप्त होने के बाद सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने इस बार उसकी दोबारा कस्टडी की मांग नहीं की और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने का आग्रह किया। अदालत ने सौरभ को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद अब ईडी ने उसे अपनी जांच के सिलसिले में पूछताछ के



लिए अदालत में पेश करने की अनुमति हासिल कर ली है। शुक्रवार को पुलिस और जांच एजेंसियों की टीम उसे रायपुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंचेगी। पेशी के दौरान ईडी उसकी कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी। आठ दिन की पूछताछ के दौरान सीबीआई ने सौरभ से महादेव ऐप के संचालन नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए वित्तीय लेन-देन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर सवाल किए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम किन-किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क में अधिकारियों, प्रभावशाली व्यक्तियों तथा अन्य लोगों की क्या भूमिका रही।

सट्टे के कारोबार से अर्जित रकम को किन बैंक खातों और विदेशी माध्यमों से इधर-उधर किया गया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली एफआईआर 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद छह अक्टूबर 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। जांच में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी के तौर पर चिन्हित किया गया।

वहीं, सीबीआई ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दूसरी ओर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार चल रहा था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके द्वारा कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई थी।



14 से 17 दिसंबर तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र

विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी तेज, अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-विधान एप्लीकेशन के इस्तेमाल का दिया प्रशिक्षण

रायपुर, यशभारत। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक आयोजित होगा। छठवीं विधानसभा के 11वें सत्र में चार दिनों के दौरान कुल चार बैठकें होंगी। सत्र में प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ विभिन्न विषयों पर सरकार से सवाल-जवाब किए जाएंगे। वहीं, विधानसभा के कामकाज को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पूरी व्यवस्था डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

इसी क्रम में विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के संचालन और उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 3 और 4 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विधानसभा की कार्यप्रणाली में डिजिटल व्यवस्था लागू करने के लिए संबंधित अमले को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेवा समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी दी। इसमें एडमिन, प्रश्न और समिति मॉड्यूल के संचालन की प्रक्रिया समझाई गई। अधिकारियों-कर्मचारियों को बताया गया कि विधायकों के प्रश्न और विभिन्न सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से किस तरह भेजी और प्राप्त की जा सकेंगी। इसके साथ ही विधानसभा से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने, सदन की कार्यवाही की जानकारी साझा करने और एप्लीकेशन की अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण में विधानसभा सचिवालय, चिप्स और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।दरअसल, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों के कामकाज को तकनीक आधारित बनाकर कागज के उपयोग को कम करना है।

न शटर तोड़ा, न ताला खोला... दीवार में सेंध लगाकर करोड़ों के गहने ले उड़े चोर

कटनी के किसना ज्वेलरी शोरूम में बड़ी वारदात ,15 करोड़ की चोरी पुलिस के लिए चुनौती







कटनी, यशभारत। माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरगवां स्थित एलआईसी के पास किसना ज्वेलर्स शो रूम में हुई करीब 12 से 15 करोड़ की चोरी ने भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय तक सनसनी मचा दी है। खबर है कि पुलिस मुख्यालय में आईजी जबलपुर से वारदात के संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने कई घंटे रुककर किसना शो रूम और पीछे लगी पहाड़ी और झाड़ियों में जाकर तफ्तीश की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कटनी में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात में किसी बाहरी चोर गिरोह का हाथ भी हो सकता है। वारदात की टाइमिंग और तरीके से जाहिर होता है कि चोर पूरी तैयारी से थे और उन्होंने करीब दो तीन दिन शो रूम की रैकी भी की होगी।

शो रूम मेन रोड पर है, लेकिन इसका पिछला हिस्सा रात्रि के बाद सुनसान इलाके में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा झाड़ियां और पहाड़ी भी लगी हुई है। चोरों ने इत्मीनान से पीछे की दीवार में छेद किया और अंदर घुसे। चोर अपने साथ अलमारी या काटने का पूरा इंतजाम भी करके आए थे। पुलिस को गैस सिलेंडर भी मिले है, जिससे जाहिर हो रहा है कि लॉकर काटने के लिए उन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल किया होगा।पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात रात्रि 3 बजे से 6 बजे के बीच की है। वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर 4 या उससे ज्यादा रहे होंगे। पीछे से शो रूम में घुसने के बाद वहां रखे सोने, चांदी तथा डायमंड के कीमती आभूषण लेकर किसी चार पहिया वाहन से फरार हुए होंगे। डॉग स्क्वाड सारी निशानदेही की पतासाजी कर रही है। बताया जाता है कि दीपावली के त्योहार के चलते शोरूम में करोड़ों रुपये का अतिरिक्त स्टॉक रखा हुआ था। शो रूम संचालक मोहन बजाज ने मीडिया को बताया कि चोरी गए आभूषणों की कीमत 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। उन्होंने कहा कि सारे आभूषण का रिकॉर्ड कम्प्यूटर पर होता है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे जब शो रूम के कर्मचारियों ने शटर उठाया, तब उन्हें इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल फोन पर सूचना दी। इस बड़ी वारदात से शहर के व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बड़े शो रूम के संचालक इस वारदात के बाद दहशत में आ गए है।

एसपी सहित पुलिस अधिकारियों ने किया निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. कमल मौर्य सहित माधवनगर थाना पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने शोरूम के अंदर से लेकर पिछले हिस्से तक का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल से पुलिस को पाना, प्लास और पेचकस सहित कुछ औजार मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। साक्ष्य जुटाने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है।

12 से 15 करोड़ के आभूषण चोरी होने की जानकारी

चोरी गए आभूषणों की कीमत को लेकर शुरुआती आंकड़ों में अंतर सामने आया है। शोरूम संचालक मोहन बजाज के मुताबिक दुकान में करीब 12 से 15 करोड़ रुपये के आभूषण रखे हुए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक के शुरुआती आकलन के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपये की ज्वेलरी चोरी होने की आशंका है। हालांकि चोरी गए आभूषणों की वास्तविक कीमत का पता स्टॉक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के मिलान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

पेपर लीक रोकने NTA का बड़ा फैसला

रिटायर्ड फौजियों की निगरानी में होंगी JEE-NEET जैसी परीक्षाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) लगातार बड़े कदम उठा रही है। अब एजेंसी परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने और एस्पिरेंट्स को भरोसा जीतने के लिए रिटायर्ड फौजियों की मदद लेने का फैसला किया है। सेना और पैरामिलिट्री से रिटायर्ड को JEE, NEET, NET, CUET जैसी बड़ी परीक्षाओं की निगरानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

दरअसल, नीट यूजी मई पेपर लीक के चलते विवादों में घिरने के बाद, एनटीए बड़े पैमाने पर सुधार और बदलाव कर रही है। 21 जून 2026 को नीट यूजी री-एग्जाम में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में सेना की मदद लेने के बाद, अब एनटीए आगे भी सेना की मदद लेने पर विचार रही है।एनटीए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) का एक परमानेंट पूल तैयार कर रही है, जिसमें सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मी, केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे। एनटीए के %एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट% (EOI) डॉक्यूमेंट में कहा गया है, %हर परीक्षा के दिन, NTA हर परीक्षा केंद्र पर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) तैनात करता है। ये ऑब्जर्वर सेंटर पर NTA का अपना प्रतिनिधि करेंगे, जो सिटी कोऑर्डिनेटर और सेंटर सुपरिंटेंडेंट से अलग होंगे। इनका काम परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा और सुचारू संचालन की निगरानी करना और सीधे NTA को रिपोर्ट करना होगा।

इसमें आगे कहा गया है, पूरे साल चलने वाली परीक्षा प्रक्रिया के दौरान इस जरूरत को समय पर और भरोसेमंद तरीके से पूरा करने के लिए, ह्वज्ञ पर्यवेक्षकों का एक स्थायी और पहले से सत्यापित (pre-verified) पूल बनाना चाहता है। इसमें सरकारी संस्थानों के सेवानिवृत्त या कार्यरत शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होंगे। इस पूल से, हर परीक्षा के लिए काफी पहले ही तैनाती के आदेश जारी किए जा सकेंगे।

अंडर-19 एशिया कप फाइनल भारत-पाकिस्तान फिर 14 नवंबर को खिताबी मुकाबला

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर अंडर-19 एशिया कप का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। 14 नवंबर को होने वाले फाइनल में दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने-सामने होंगी। पिछले संस्करण के फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रन के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया था। इस बार भारतीय टीम के पास पिछली हार का बदला लेने और खिताब जीतने का मौका होगा। गुरुवार को ओमान के मस्कट में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 227 रन बनाए। टीम की ओर से नुमान सालारजई और शाह फैसल रहीमी ने 51-51 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। भारत की ओर से ईशान सूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। आर्यन सावसानी ने भी 2 विकेट लेकर अफगानिस्तान की रन गति पर अंकुश लगाया।228 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। भारत ने महज 36.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने 57 गेंदों में 51 रन की उपयोगी पारी खेली। वहीं कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 93 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वीके विनीत 57 रन बनाकर नाबाद रहे।



लक्ष्य रायचंदानी- 93 रन

खुदरा महंगाई ने फिर पकड़ी रफ्तार, अक्टूबर में 6.09 फीसदी पर पहुंची दर

खाद्य महंगाई 8.94 फीसदी हुई, प्याज के दाम में 116 फीसदी का उछाल

नई दिल्ली, एजेंसी। अक्टूबर में महंगाई से राहत की उम्मीद लगाए बैठे आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। सब्जियों, अनाज और खाने-पीने की दूसरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी के चलते देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है। सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी। इस तरह एक महीने के भीतर महंगाई में 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि करीब दो साल बाद खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निर्धारित 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। इससे आम परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ने के साथ ही केंद्रीय बैंक के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। ऐसे में सब्जियों, अनाज और अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई पर भी तेजी से असर पड़ता है।अक्टूबर में सबसे ज्यादा महंगाई प्याज की कीमतों में दर्ज की गई। प्याज के दाम सालाना आधार पर 116.22 फीसदी बढ़ गए। इसके अलावा लहसुन 60.74 फीसदी, अदरक 48.32 फीसदी और नींबू 47.30 फीसदी महंगे हुए। चांदी के आभूषणों की कीमतों में भी 52.39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सोनिया ने 1984 के सिख कत्लेआम पर जनरल वैद्य को ठहराया जिम्मेदार, फूलका ने उठाए सवाल

लुधियाना, एजेंसी। *कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग-ए जर्नी ऑफ लव' के 17वें अध्याय में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर किए गए खुलासों से पंजाब की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़की हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सेना बुलाने के आदेश 31 अक्टूबर की रात ही दे दिए गए थे, लेकिन तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल एएस वैद्य ने दिल्ली के नजदीकी सैन्य ठिकानों से सेना बुलाने के बजाय देहरादून से सैन्य टुकड़ियां मंगवाईं। इस फैसले के कारण सेना की तैनाती में देरी हुई और हिंसा पर काबू पाने में समय लगा।*



सोनिया गांधी के इन दावों पर भाजपा नेता और 1984 के सिख दंगा पीड़ितों की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिल्ली में पहले से ही करीब 6100 सैनिक मौजूद थे, तो उन्हें दंगों के दौरान सड़कों पर क्यों नहीं उतारा गया? फूलका ने यह भी सवाल किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हिंसा के बाद यह बयान क्यों दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। उन्होंने कहा कि इस बयान के जरिए सिखों के नरसंहार को जायज ठहराने की कोशिश की गई थी। ऐसे में केवल सेना की देरी को जिम्मेदार बताकर उस समय की राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में बिगड़े हालात और दिल्ली में भड़की हिंसा का जिक्र करते हुए अपने परिवार का पक्ष रखा है। उन्होंने लिखा है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजधानी सहित देश के कई हिस्सों में तनाव फैल गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा। किताब के मुताबिक, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद 31 अक्टूबर की रात राजीव गांधी ने राष्ट्रीय टेलीविजन के माध्यम से देश को संबोधित किया था। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की थी। सोनिया गांधी का दावा है कि राजीव गांधी ने एक और दो नवंबर को भी अलग-अलग माध्यमों से लोगों से हिंसा रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की थी। सोनिया ने लिखा है कि तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल एएस वैद्य को इंदिरा गांधी की हत्या वाली रात ही दिल्ली में सेना तैनात करने के निर्देश दे दिए गए थे।

मुंबई में फिर बम धमाकों की धमकी, अमिताभ बच्चन का बंगला 'जलसा' भी निशाने पर

मुंबई, यशभारत। मुंबई में एक बार फिर बम धमाकों की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इस बार धमकी भरे ईमेल में मुंबई के कई महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक स्थानों के साथ बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले 'जलसा' को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखाओं, मेयर कार्यालय, एक अदालत और महालक्ष्मी स्टेडियम का भी उल्लेख किया गया है। ईमेल में गायक एवं अभिनेता दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रमों को लेकर भी धमकी दी गई है। संदेश के बाद संबंधित स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच अभियान चलाया गया। हालांकि, शुरुआती जांच में किसी भी स्थान से संदिग्ध वस्तु या गतिविधि मिलने की जानकारी नहीं है।

किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले



किश्तवाड़, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से अचानक लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) के शव बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। दोनों के शव गोलियों से छलनी हालत में बरामद किए गए हैं. खास बात यह है कि उनके सर्विस हथियार मौके से नहीं मिले हैं. इससे घटना में आतंकियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी किसी आतंकी हमले की पुष्टि नहीं की है. मृतकों की पहचान ऋषिपाल और बॉबी चंद के रूप में हुई है

दोनों स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का हिस्सा थे और सेना के एक दल को रिलीव करने के लिए जा रहे थे। उनके शव मिलने के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, किश्तवाड़ जिले के मारवाह क्षेत्र के देहरना जंगल में फायरिंग की आवाज सुनाई देने के बाद दोनों एसपीओ अचानक लापता हो गए थे। दोनों कियार दच्छन से अपर रिज देहरना के इंदरवन इलाके में बसनान स्थित सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम को रिलीव करने के लिए रवाना हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक, वे कियार कैंप से ढारना-मारवाह स्थित सेना की चौकी की ओर निकले थे, लेकिन निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचे। शुरुआत में दोनों जवानों के मोबाइल फोन पर संपर्क हो रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उनके फोन बंद हो गए। इसके बाद उनकी सुरक्षा और ठिकाने को लेकर चिंता बढ़ गई। पुलिस और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने संयुक्त रूप से दुर्गम पर्वतीय और जंगल क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की टीमें तैनात कर दोनों की तलाश की जा रही थी। आखिरकार तलाशी अभियान के दौरान दोनों के शव बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक, दोनों के शरीर पर गोलियों के निशान मिले हैं। इस घटना ने किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं

1.31 करोड़ की राशि और बंधक भूमि विवाद आगामी चुनाव को देखते हुए फैलाया जा रहा है भ्रामक प्रचार



इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड से. 6 के अध्यक्ष बृजबिहारी मिश्र ने निराधार आरोपों का खंडन करते हुए सार्वजनिक किए तथ्यात्मक दस्तावेज

1.31 करोड़ का भुगतान किसी निजी समझौते का नतीजा नहीं, बल्कि कानूनी प्र िया का हिस्साः स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा बंधक जमीन की खरीदी बिक्री पर स्टे आज भी प्रभावी

भिलाई। इस्पात कर्मचारी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, सेक्टर-6, के अध्यक्ष बृजबिहारी मिश्र ने आगामी संचालक मंडल चुनाव को ध्यान में रखते हुए कतिपय लोगों द्वारा किए जा रहे कथित मनगढंत प्रचार को भ्रामक और निराधार बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वास्तविक तथ्यों और न्यायिक आदेशों की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि संस्था के प्रति जवाबदेही और सदस्यों के प्रति पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सच को सामने रखना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यह विवाद किसी व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि मार्च 1984 में %स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था% को दिए गए 41 लाख के ऋण से जुड़ा हुआ है, जिसके बदले 14.04 एकड़ भूमि बंधक रखी गई थी। करीब 20 वर्ष पहले तत्कालीन संचालक मंडल की लापरवाही के कारण इसमें से लगभग 5 एकड़ जमीन ऋण लेने वालीं संस्था द्वारा बेच दी गई थी, अभी 9 एकड़ जमीन बची है। ऋण वापसी न होने पर वर्ष 2007 से न्यायिक कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद न्यायालय उप पंजीयक ने (2012), न्यायालय पंजीयक ने (2016), न्यायालय सहकारिता अधिकरण बिलासपुर ने (2017 व 2019) और माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने (2019) ने संस्था के पक्ष में आदेश दिए और विपक्षी की याचिकाओं/आवेदनों को खारिज किया।

1.31 करोड़ का निर्धारण और खाते में जमा होना।

उन्होंने कहा कि यह राशि अध्यक्ष की निजी इच्छा या किसी गुप्त समझौते से तय नहीं हुई है। न्यायालय संयुक्त पंजीयक, दुर्ग संभाग के दिनांक 22.07.2022 के आदेश के अनुपालन में, जिसमें साधारण ब्याज के आधार पर सनदी लेखाकार से गणना कराकर राशि जमा करने का उल्लेख था, ऋण लेने वाली संस्था ने बिना किसी डिमांड के स्वयं 1 अगस्त 2022 को 1.31 करोड़ ऋ्लत्स्के माध्यम से सोसाइटी के खाते में जमा किए थे।

संचालक मंडल का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय

उन्होंने कहा कि खाते में राशि आने के बाद दिनांक 03.08.2022 को संचालक मंडल की आपात बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खाते में जमा राशि को यथावत रखते हुए न्यायालय संयुक्त पंजीयक दुर्ग संभाग के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। इस बैठक में अफवाह फैलाने वाले तथा तथ्यहीन पर्चा/पोस्टर लगाने वाले संचालक मंडल के सदस्य पवन कुमार साहू भी उपस्थित थे। अतः इस सामूहिक निर्णय को अध्यक्ष की व्यक्तिगत मिलीभगत बताना पूरी तरह से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का कुत्सित प्रयास है।

न्यायिक स्थिति का सविस्तार उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि सस्था के हिती

कानूनी संघर्ष को हर स्तर पर जारी रखा गया। सहकारिता अधिकरण में वांक्षित राहत न मिलने पर सोसाइटी ने उच्च न्यायालय बिलासपुर (WP227/4067/2022) का दरवाजा खटखटाया, जहाँ दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद बंधक भूमि पर किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित करने अर्थात जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक (स्टे) लगा दी। इसके खिलाफ ऋण लेने वालीं संस्था स्मृति गृह निर्माण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, में दायर विशेष अनुमति याचिका (स्क्क6548/2023) को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को तीखी टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया।

अध्यक्ष मिश्र ने कहा कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा हमारी याचिका पर जारी स्थगन आदेश (दिनांक, 21.09.2022) प्रभावी है (अर्थात बंधक जमीन के क्रयविक्रय पर रोक है) और प्रकरण अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हो रहा है। राजस्व अभिलेखों में बंधक जमीन आज भी सोसाइटी के पक्ष में बंधक दर्ज है।

सुरक्षा के पहरे में सरकारी खजाना, कलेक्टर ने खुद परखी कोषालय की व्यवस्था; स्टांप से स्ट्रांग रूम तक हुई सघन जांच

छह-माही निरीक्षण में हर रिकॉर्ड और बहुमूल्य सामग्री का किया मिलान, जांच में व्यवस्थाएं मिलीं दुरुस्त; लापरवाही की गुंजाइश नहीं रखने के दिए निर्देश।



यश भारत

बालोद। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी जवाबदेही को परखने कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर स्थित जिला कोषालय के मुद्रांक भंडार एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा इंतजामों से लेकर स्टांप के सुरक्षित भंडारण और अभिलेखों के संधारण तक हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 39 के तहत निर्धारित छह-माही निरीक्षण में स्ट्रांग रूम में रखे नॉन-ज्यूडिशियल, ज्यूडिशियल, रेवेन्यू, स्पेशल एडेसिव और नोटरी स्टांप का अवलोकन किया गया। साथ ही बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेट, पैडलॉक, दोहरी चाबियों के पैकेट और चेकरोल का भी मिलान किया गया। निरीक्षण में सभी सामग्रियां सुरक्षित और रिकॉर्ड सुव्यवस्थित पाए गए। व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा प्रबंधों और अभिलेखों के रखरखाव में निरंतर सजगता बरती जाए। नियमों का पालन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कार्यप्रणाली का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

इस दौरान अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, जिला कोषालय अधिकारी सोमेश शोरी, खजांची टिकेश्वर सिंह निषाद सहित संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

रिसाली, भिलाई-3 चरोदा एवं नगर पालिका जामुल की फार्म जमा करने की तिथि बढ़ाई जाए



दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अली हुसैन सिद्दीकी ने आवेदन देकर उनसे मांग किया है कि नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा एवं नगर पालिका जामुल की निर्वाचक नामावली प्रारूप क-1 , ख और ग फार्म जमा करने की तिथि बढ़ाया जाए ।

सिद्दी की ने आवेदन के द्वारा निरवाचान अधिकारी को अवगत कराया है।की।कि,छत्तीसगढ़ राज्य और भारत निर्वाचन आयोग के बीच सामंजस्य की कमी की वजह से अब तक 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के द्वारा मतदाता सूची मे नाम जोड़ने हेतु निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन और शहर के मतदान केंद्रों में बी एल ओ के समक्ष फॉर्म-6 जमा किया है । जो एपिक नंबर जारी नहीं होने की वजह से लंबित है।

इससे दुर्ग जिला का नगर पालिक निगम, भिलाई, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा, और नगर पालिका जामुल के हजारों युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाएगा और ऋ्ठ्ठ्र अपने शहर के प्रथम नागरिक महापौर और पार्षद पद के लिए दिसम्बर 2026 में होने वाले चुनाव में वोट नहीं कर पायेगे ।

अवगत हो कि दिनांक 21 अक्टूबर 2026 से भारत निर्वाचन/ छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट फ्रीज है।इस वजह से 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के द्वारा मतदाता सूची मे नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन और शहर के मतदान केंद्रों में बी एल ओ के समक्ष 23 अक्टूबर 2026 से 3 नवंबर 2026 तक फॉर्म- 6 जमा किया है । जो एपिक नंबर जारी नहीं होने की वजह से लंबित है।

प्रारूप - क-1 जमा करने की 11 नवंबर 2026 अंतिम तारीख है।

अगर तारीख बढ़ाई नहीं गई तो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं का नाम स्थानीय नगर पालिका निगम की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएगा।

भिलाई निगम की बात किया जाए तो फॉर्म -6 के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या 4 से 5 हजार हो सकती है।

3 नवंबर 2026 को इस विषय को भिलाई निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्ति के माध्यम से इस विषय को जिला निर्वाचन विभाग दुर्ग के संज्ञान में भी लाया गया था,जिस पर जिला निर्वाचन विभाग ने आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन दिया गया था,आज 12 नवंबर 2026 निकाय चुनाव के मतदाता सूची में नाम जोड़ने का फॉर्म क-1 जमा करने की अंतिम तारीख है। लेकिन आपत्ति और आवेदन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

जिससे भिलाई निगम क्षेत्र के ही 4 से 5 हजार की संख्या में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा समय पर आवेदन करने के बावजूद निगम चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। इसी तरह नगर निगम रिसाली, भिलाई -3 चरोदा , बीरगांव और जामुल के हजारों ऋ्ठ्ठ्र भी मतदान नहीं कर पाएंगे। नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा एवं जामुल की निर्वाचक नामावली प्रारूप क-1 , ख और ग जमा करने की तिथि को बढ़ाए जाने की मांग की है।

डीएमएफ फंड से कोचिंग करने गए छात्रों की पढ़ाई पर संकट, फीस नहीं मिलने पर एलन इंस्टीट्यूट ने रोकी क्लास

कोरबा। जिले के होनहार विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) मद से रायपुर के एलन इंस्टीट्यूट भेजा गया था, लेकिन अब फीस भुगतान में देरी के चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। संस्थान ने बकाया फीस जमा नहीं होने का हवाला देते हुए विद्यार्थियों की कक्षाएं लेने से इनकार कर दिया है। इस स्थिति से परेशान अभिभावक गुरुवार को बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से तत्काल फीस जमा कराने की मांग की।

जानकारी के मुताबिक, डीएमएफफंड के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर भेजने की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत 26 मई 2025 को बच्चों को कलेक्ट्रेट से रवाना किया गया था। उस समय विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद थी, लेकिन अब संस्थान की फीस बकाया होने से उनकी पढ़ाई पर विराम लग गया है।

अभिभावकों की दो टूक, फीस जमा होने तक नहीं भेजेंगे बच्चे

बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से नाराज अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। उनका कहना है कि जब तक संस्थान की पूरी बकाया फीस जमा नहीं की जाती, तब तक वे अपने बच्चों को रायपुर नहीं भेजेंगे। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर चक्काजाम करने की भी बात कही गई है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि संस्थान को अब तक 2 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष बकाया राशि भी जल्द जमा कराने की प्रक्रिया की जाएगी। दूसरी ओर, अभिभावकों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि फीस भुगतान में देरी का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 26 मई 2025 को बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर रायपुर रवाना हुए इन विद्यार्थियों के सामने अब पढ़ाई जारी रखने को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।

बिना नतीजा के सेल एन जे सी एस की बैठक हुई खत्म

मैनेजमेंट ने कहा- हलफनामे में बोल चुका हूं, नहीं देंगे एरियर यूनियन नेताओ ने प्रबंधन की बात को किया खारिज

यश भारत

भिलाई। सेल कर्मचारियों को बकाया एरियर नहीं मिलेगा। सेल प्रबंधन ने एनजेसीएस यूनियन नेताओं की बैठक बुलाई,जो बेनतीजा समाप्त हो गई है। गुरुवार को सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। दोपहर सवा 3 बजे समाप्त भी हो गई। प्रबंधन जोर दिए हुए था कि एचआरए के मुद्दे पर चर्चा की जाए। लेकिन, इंटक, बीएमएस, एटक, सीटू, एचएमएस के नेताओं ने एक सिरे से प्रबंधन की बात को खारिज कर दिया।

सभी नेताओं ने कहा-एरियर पर बात कीजिए, इसके अलावा किसी पर बात नहीं होगी। इस पर सेल प्रबंधन ने कहा-हम लोगों ने कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं कि एरियर नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब इस विषय पर बात नहीं कर सकते हैं। मामला कोर्ट मे है। जब तक कोर्ट से कुछ तय नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं बोल सकते।

प्रबंधन की बातों को सुनने के बाद बीएमएस से हिमांशु शेखर बल, एचएमएस से राजेंद्र सिंह, सीटू से बिश्वरूप बनर्जी, एटक से डी. आदिनारायण, इंटक से हरजीत सिंह ने कहा-फुल एनजेसीएस मीटिंग बुलाइए।

प्रबंधन ने इस पर जवाब दिया कि आप लोग 2027 के वेज के लिए तैयार हो जाइए। यूनियन नेताओं ने पलटकर जवाब दिया कि एरियर जब तक नहीं मिलेगा, किसी तरह के समझौते पर अब कोई साइन नहीं करेगा

रायपुर के ऐतिहासिक तालाबों के नाम परिवर्तन पर रोक की मांग, निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन



यश भारत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक तालाबों और नदी घाटों के मूल नाम बदलने के विरोध में छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने मंगलवार को नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कटोरा तालाब, तेलीबांधा तालाब और महादेव घाट के नामों से छेड़छाड़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के तालाब और घाट केवल जलस्रोत नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, परंपरा और पूर्वजों की विरासत से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर हैं। इनके नाम बदलना सांस्कृतिक पहचान के साथ छेड़छाड़ है।

संगठन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि तालाबों के मूल नामों को बदलने की प्रवृत्ति पर रोक के लिए प्रशासन को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत से परिचित रह सकें। पदाधिकारी उषा श्रीवास ने कहा कि प्रवासियों को छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने के लिए तालाबों और घाटों का उपयोग करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धार्मिक आस्था के नाम पर मूल नाम बदलकर 'छठ घाट' या 'झूलेलाल सरोवर' लिखना उचित नहीं है।

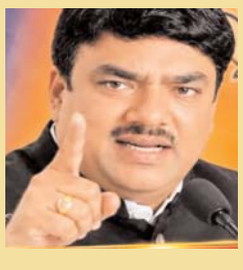
संगठन ने मांग की है कि कटोरा तालाब पर लिखे गए 'झूलेलाल सरोवर' नाम को हटाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा और निगम का घेराव करेगा।

खैरागढ़ में प्रशासन की सख्ती, तीन पटवारी निलंबित; 57 का वेतन रोका

खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, शासकीय आदेशों की अवहेलना और निर्धारित समय-सीमा में जिम्मेदारी पूरी नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि काम पर वापस नहीं लौटने और सरकारी निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन के अनुसार, जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसका असर डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों पर पड़ रहा है। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर होना जरूरी है। कार्य प्रभावित होने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 30 अक्टूबर को हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर शासकीय कामकाज संभालने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही तहसीलदार को सूचना देकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने को कहा गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समय तक काम पर नहीं लौटने वालों की अनुपस्थिति अनधिकृत मानी जाएगी और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया था। निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत शामिल हैं। उन पर स्वामित्व योजना के तहत प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और दो गांवों के दस्तावेज जमा नहीं करने का आरोप है। इसके कारण पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख वितरित करने में देरी हुई। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से जुड़े आवेदन भी उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए। वहीं, छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन लंबित रखने का मामला सामने आया है। इसी तरह साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने का आरोप है। उन्हें 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद उन्होंने वहां पहुंचकर प्रभार ग्रहण नहीं किया।

खड़गे के बयान पर भड़के कन्हैया सोनी , बोले तुष्टीकरण के लिए हिंदू आस्था से खिलवाड़

नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और आस्थाओं के प्रति कांग्रेस नेताओं की सोच बार-बार उजागर हो रही है



दुर्ग। दीपावली जैसे हिंदू धर्म के पवित्र पर्व को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्हैया सोनी ने खरगे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़कर देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता एक विशेष वर्ग को खुश करने के उद्देश्य से बार-बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। यह महज शब्दों का चयन या अनजाने में हुई गलती नहीं, बल्कि सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।

कन्हैया सोनी ने कहा कि दीपावली हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। इसका अपना धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन से लेकर माता लक्ष्मी की आराधना तक, दीपावली सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक है। ऐसे पवित्र पर्व को किसी दूसरे धर्म के त्योहार से जोड़कर संबोधित करना हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी बयानबाजी की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि कांग्रेस वास्तव में सभी धर्मों का समान सम्मान करने की बात करती है, तो उसे हिंदू धर्म, सनातन परंपराओं और हिंदू देवी-देवताओं के प्रति भी समान संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

यह पहली बार नहीं, बार-बार सामने आती है ऐसी बयानबाजी- कन्हैया सोनी ने कहा कि हिंदू धर्म, देवी-देवताओं और सनातन संस्कृति को लेकर विवादित टिप्पणियां करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। कांग्रेस के अलग-अलग नेता समय-समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं, जिनसे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। विवाद खड़ा होने के बाद कांग्रेस नेता अपने बयानों का बचाव करने लगते हैं, लेकिन मूल सवाल वहीं बना रहता है कि आखिर हिंदू धर्म और उसकी आस्थाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति में तुष्टिकरण की प्रवृत्ति इतनी हावी हो चुकी है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की जाती है। कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए कि हिंदू समाज की आस्था कोई राजनीतिक प्रयोग का विषय नहीं है।

हिंदू आस्था के सम्मान पर कांग्रेस को देना चाहिए जवाब- भाजपा नेता ने कहा कि भारत में सभी धर्मों और उनके त्योहारों का सम्मान होना चाहिए। ईद, क्रिसमस और अन्य धार्मिक पर्वों की अपनी पहचान और महत्ता है, उसी तरह दीपावली, होली, नवरात्रि और अन्य हिंदू पर्वों की भी अपनी विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान है। किसी भी धर्म की पहचान को दूसरे धर्म के संदर्भ में परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। कन्हैया सोनी ने कहा कि कांग्रेस को केवल राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की चिंता करने के बजाय देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। धार्मिक सद्भाव की बातें करने वाले नेताओं को अपने शब्दों और बयानों में भी वही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म करोड़ों लोगों की आस्था और भारत की सांस्कृतिक विरासत का आधार है। हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक या आपत्तिजनक टिप्पणियों को सामान्य राजनीतिक बयानबाजी बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेतृत्व को इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, खलीबा में नवीन धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति से सैकड़ों अन्नदाताओं को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री साय के संवेदनशील निर्णय से किसानों को मिली बड़ी सौगात, अब धान बेचने के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी दूरी की दौड़

यश भारत

रायपुर। किसानों की मेहनत से उपजी फसल को बेचने के लिए अब उन्हें लंबी दूरी तय करने और परिवहन की परेशानियों से जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सरगुजा जिले के ग्राम खलीबा में देखने को मिला है। यहां किसानों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए नवीन धान उपार्जन केंद्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से खलीबा सहित आसपास के 11 गांवों के किसानों में खुशी का माहौल है। क्षेत्र के लगभग 416 पंजीकृत किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति उन छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष राहत लेकर आई है, जिन्हें अब तक अपनी उपज बेचने के लिए दूरस्थ खरीदी केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता था। वाहन की व्यवस्था, परिवहन पर अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी जैसी समस्याएं किसानों के लिए बड़ी चुनौती थीं। अब अपने क्षेत्र में ही खरीदी केंद्र की सुविधा मिलने से धान विक्रय की प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक होगी।

किसानों की समस्या का हुआ समाधान

ग्राम खलीबा निवासी प्रगतिशील कृषक एवं उपसरपंच नितेश कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र दूर होने के कारण किसानों को लंबे समय से अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर छोटे किसानों के पास धान परिवहन के लिए स्वयं के साधन नहीं होने से उन्हें वाहन की व्यवस्था करने में कठिनाई होती थी। कई किसानों को पंजीयन संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा किसानों की मांग मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तक पहुंची और राज्य शासन ने खलीबा में नवीन धान उपार्जन केंद्र की स्वीकृति प्रदान की।

11 गांवों के किसानों के लिए सुविधाजनक बनेगा खलीबा उपार्जन केंद्र

नवीन धान खरीदी केंद्र खलीबा में ग्राम



खलीबा, अजिरमा, कुल्हाड़ी, चठिरमा, ठाकुरपुर, बढ़नीझरिया, बलसेड़ी, बिसुनपुर खुर्द, भगवानपुर कला, भगवानपुर खुर्द एवं मेन्ड्राखुर्द के किसानों को सुविधा मिलेगी। सिंह ने बताया कि खलीबा आसपास के गांवों के मध्य स्थित है, जिससे यह स्थान धान खरीदी केंद्र के लिए सुविधाजनक है। वर्तमान में क्षेत्र के लगभग 416 किसान पंजीकृत हैं। नवीन खरीदी केंद्र की सुविधा मिलने से आने वाले वर्षों में पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

धान का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति हो रही मजबूत

प्रगतिशील कृषक नितेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हित में लिए जा रहे निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को धान का बेहतर मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी तथा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलने वाली राशि का किसानों को लाभ मिला। खेती में बढ़ती लागत और विपरीत परिस्थितियों के बीच उपज का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों को आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने सुनी किसानों की मांग, ग्रामीणों ने जताया आभार

नवीन धान उपार्जन केंद्र की स्वीकृति मिलने पर प्रगतिशील कृषक एवं उपसरपंच नितेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र के किसान कई वर्षों से धान बेचने में परेशानियों का सामना कर रहे थे। वाहन नहीं मिलने और दूर खरीदी केंद्र तक जाने में काफी दिक्कत होती थी। हमने लगातार प्रयास कर अपनी मांग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हमारी मांग पूरी करते हुए खलीबा में नवीन धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति दी है। इससे आसपास के गांवों के सैकड़ों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हम सभी किसान भाइयों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णु भैया का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए नवीन धान उपार्जन केंद्रों की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयास ग्रामीण अंचलों में कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मदिरा प्रेमियों ने जमकर छलकाए जाम!



शराब की बिक्री में करीब 10 फीसदी का इजाफा

रायपुर । दीपावली का त्योहार शराब कारोबार के लिहाज से भी रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ। दीपावली के मौके पर मदिराप्रेमियों ने जमकर शराब की खरीदारी की। आलम यह रहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार शराब की बिक्री में करीब 10 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है। दीपावली के जश्न में जहां बाजारों में रौनक देखने को मिली, वहीं शराब दुकानों में भी खरीदारों की भीड़ उमड़ती रही। त्योहार के दौरान शराब की जमकर बिक्री हुई और पिछले साल का रिकॉर्ड पीछे छूट गया। मिली जानकारी के मुताबिक, गत वर्ष की तुलना में इस दीपावली पर शराब की बिक्री में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बिक्री के इन आंकड़ों ने एक बार फिर त्योहारों के दौरान शराब की खपत को लेकर चर्चा तेज कर दी है। फिलहाल दीपावली पर शराब बिक्री में हुई इस बढ़ोतरी ने आबकारी विभाग के राजस्व में भी इजाफे के संकेत दिए हैं।

महलोई का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में होगा विकसित, चौधरी ने किया भूमिपूजन

विद्यार्थियों से संवाद कर शिक्षा, ज्ञान और कौशल के महत्व पर की चर्चा

यश भारत

रायपुर। रायगढ़ जिले के महलोई स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में आज भूमिपूजन किया गया। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि विद्यालय का मॉडल स्कूल के रूप में विकास विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल है।



भूमिपूजन के बाद चौधरी ने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान और कौशल तभी सार्थक होते हैं, जब उनका उपयोग सही दिशा में किया जाए। विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बच्चों को अपनी रुचि और क्षमताओं को पहचानकर भविष्य निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। चौधरी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने और नए अवसरों तक पहुंचने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालय में बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायक होंगे।

मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होने के बाद महलोई के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर शिक्षा का लाभ मिलेगा। यह पहल विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों को अपने सपनों और भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्रदान करेगी।

वक्फ बोर्ड की 5,000 करोड़ की संपत्तियों पर सीबीआई जांच का दावा खोखला,आरटीआई में खुलासा : कांग्रेस

यश भारत



रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और कथित फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच कराने के दावे की पोल आरटीआई से खुल गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश की 5,723 संपत्तियों पर अवैध कब्जे और लगभग 5,000 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य का हवाला देते हुए सीबीआई जांच कराने की बात कही गई थी, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बोर्ड कार्यालय ने ऐसी किसी फाइल या दस्तावेज के उपलब्ध होने से ही इनकार कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ''सीबीआई जांच के दावे, लेकिन प्रस्ताव की फाइल तक नहीं''वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जून 2025 में रायपुर सहित प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी रजिस्ट्री की सीबीआई जांच कराने की बात कही थी। इसके बाद प्रदेशभर की 5,723 संपत्तियों पर अवैध कब्जे और लगभग 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य का दावा करते हुए जांच का प्रस्ताव शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने की बात सामने आई थी। लेकिन आरटीआई के तहत वक्फ बोर्ड से सीबीआई जांच के लिए भेजी जाने वाली फाइल, प्रकरणों की सूची और प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गईं तो बोर्ड कार्यालय का जवाब चौंकाने वाला था। कार्यालय ने लिखित रूप में बताया कि ''÷उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।÷''

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयानों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,000 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर किरायेदार काबिज हैं, लेकिन किराया नहीं दे रहे हैं। इन संपत्तियों से सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना जताई गई थी, जबकि वर्तमान में बोर्ड को महज 5 लाख रुपये किराया मिलने का दावा किया गया। बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें 125 ने जवाब दिया, जबकि 437 को 30 मई 2025 तक अंतिम नोटिस भेजने की बात कही गई थी।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने, फर्जी रजिस्ट्रियों की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे लगातार किए गए। प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र को सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेजने की बात भी कही गई। लेकिन आरटीआई के जवाब से यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब बोर्ड कार्यालय में जांच संबंधी कोई फाइल या दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं हैं, तो सीबीआई जांच कराने की प्रक्रिया आखिर कहां तक पहुंची? प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों और 5,723 मामलों से जुड़ा यह गंभीर विषय केवल घोषणाओं और दावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वक्फ संपत्तियों की वास्तविक स्थिति, कथित कब्जों, किराया वसूली और सीबीआई जांच के प्रस्ताव पर बोर्ड को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जवाब देना चाहिए। आखिर संपत्तियों को मुक्त कराने और कथित अनियमितताओं की जांच कराने के नाम पर अब तक क्या ठोस कार्रवाई हुई है?

देवउठनी एकादशी पर 20 को स्थानीय अवकाश घोषित

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जारी किया आदेश, रायपुर जिले के शासकीय कार्यालयों में रहेगा अवकाश रायपुर, 12 नवंबर 2026। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने देवउठनी एकादशी पर्व के अवसर



पर 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को रायपुर जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को घोषित स्थानीय अवकाश नवा रायपुर अटल नगर एवं रायपुर शहर (राजधानी) स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं को छोड़कर रायपुर जिले के शेष सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में लागू रहेगा।

बलरामपुर जिले में जनजातीय लोककला और संस्कृति का भव्य संगम

बलरामपुर। जिले में जनजातीय लोककला और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला।जिला स्तरीय लोकनृत्य महोत्सव में जिलेभर से पहुंचे कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में ओकरा, धनजी और करचा के नर्तक दलों ने बाजी मारी। विजेता दल अब राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

बलरामपुर जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। मांदर और ढोल-नगाड़ों की थाप पर कलाकारों ने पारंपरिक लोकनृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता में ग्राम ओकरा ने प्रथम, धनजी ने द्वितीय और करचा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विधायक ने कहा कि जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है।



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा ने कहा कि जनजातीय संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान है। आधुनिकता के दौर में भी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना जरूरी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपनी लोककला, भाषा और रीति-रिवाजों से जुड़े रहने की अपील की

प्रतियोगिता में कलाकारों के प्रदर्शन के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया। राजपुर विकासखंड के ग्राम ओकरा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 50 हजार रुपये जीते वहीं कुसमी के धनजी गांव को दूसरा और करचा गांव को तीसरा स्थान मिला। तीनों विजेता दल अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे.

जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने का एक प्रयास भी है, ऐसे आयोजनों से ग्रामीण अंचलों में छिपी प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है और नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली परंपराओं से परिचित होती है।

गुमशुदगी की सूचना पर प्रभावी कार्रवाई, हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा; दो आरोपी गिरफ्तार, मृतक का शव बरामद

यश भारत

रायपुर। थाना तेलीबांधा क्षेत्र में एक युवक के लापता होने की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल संवेदनशीलता एवं गंभीरता से कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्रार्थिया द्वारा सूचना दी गई कि उसका पुत्र निरंजन पाल दिनांक 10 नवंबर को रात्रि लगभग 8-30 बजे से घर से लापता है। सूचना पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल पतासाजी एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर राजा नायडू से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने मामले की परतें खोलते हुए विनोद दांडेकर की संलिप्तता का पता लगाया।



पूछताछ में सामने आया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की हत्या में निरंजन पाल के शामिल होने के संदेह के चलते विनोद दांडेकर उससे पुरानी रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते विनोद दांडेकर ने राजा नायडू के साथ मिलकर निरंजन पाल को कमल विहार सेक्टर-13 बुलाया, जहां दोनों ने उसे शराब पिलाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य एवं पहचान छिपाने के उद्देश्य से मृतक के कपड़े जलाकर शव को गटर में फेंक दिया तथा उसकी एक्टिवा को बाकल नदी के पास छिपा दिया।

पुलिस द्वारा त्वरित एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों राजा नायडू एवं विनोद दांडेकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक निरंजन पाल का शव बरामद कर लिया गया। साथ ही घटना से संबंधित जले हुए कपड़े एवं मृतक की एक्टिवा भी बरामद की गई है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी राजा नायडू थाना तेलीबांधा का गुंडा-बदमाश है। तेलीबांधा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सतत पतासाजी एवं प्रभावी विवेचना के परिणामस्वरूप गुमशुदगी के प्रकरण में हत्या का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा मृतक का शव एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

सोशल मीडिया के चक्कर में स्टंटबाजी पड़ी भारी

सड़क पर खतरनाक स्टंट और अशोभनीय हरकत करने वाले 5 युवक गिरफ्तार, च धरनगर पुलिस ने भेजा जेल

रायगढ़। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने का जुनून पांच युवकों को भारी पड़ गया। रायगढ़ शहर की सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंटबाजी और अशोभनीय हरकतें करते हुए वीडियो बनाना युवकों को महंगा पड़ गया। चक्रधरनगर पुलिस ने वीडियो के आधार पर पांचों युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी युवकों को एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद पांचों को जेल दाखिल करा दिया गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने साफ संदेश दिया है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



मामला 9 नवंबर की रात का है, जब रायगढ़ शहर में शहीद हेमू कलाणी चौक से चक्रधरनगर चौक की ओर दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पांच युवक जा रहे थे। इस दौरान युवक चलती बाइक पर खतरनाक स्टंटबाजी करने के साथ सार्वजनिक सड़क पर अशोभनीय हरकतें कर रहे थे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे थे।

युवकों की इन हरकतों को एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसकी जानकारी चक्रधरनगर थाना प्रभारी को दी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा ने वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कराई और इसकी जानकारी एसएसपी शशि मोहन सिंह को दी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने पांचों युवकों को उनके अभिभावकों के साथ थाने बुलाया और सार्वजनिक सड़क पर इस तरह की हरकतों के खतरों से अवगत कराते हुए समझाइश दी।

इसके बावजूद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पांचों के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस एवं 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। सभी को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक कार्रवाई की जद में आने वाले युवकों में विद्याधर देवांगन, ऋतिक बरेठ, आशीष चौहान, आकाश शर्मा और मनीष शर्मा शामिल हैं। सभी की उम्र लगभग 21 वर्ष बताई गई है।

रायगढ़ पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियो और गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों और वाहन चलाने के तौर-तरीकों पर ध्यान दें।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से साकार हो रहे श्रमिक परिवारों के बच्चों के सपने

291 श्रमिक परिवारों के बच्चे निजी आवासीय विद्यालयों में प्राप्त कर रहे नि: शुल्क शिक्षा

यश भारत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रमिक परिवारों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नई राह प्रशस्त कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 291 श्रमिक परिवारों के बच्चे प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें कक्षा छठवीं के 200 विद्यार्थी तथा कक्षा सातवीं के 91 विद्यार्थी शामिल हैं। ये बच्चे प्रदेश के 19 निजी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। यह योजना 2025-26 मे प्रारम्भ हुई थी, जिसमें 2 वर्षों मे ही 291 बच्चों इस योजना का लाभ दिया गया है। योजना के माध्यम से श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को सीबीएसई एवं आईसीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में अध्ययन का अवसर मिल रहा है, जिससे वे आधुनिक शिक्षा के साथ बेहतर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर सकें। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक परिवारों की आर्थिक परिस्थितियां उनके बच्चों की शिक्षा और सपनों के आड़े न आएं। आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें तथा भविष्य में समाज और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की यह पहल श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ शिक्षा के माध्यम से समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब श्रमिक का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को नई उड़ान देगा।

चिंतन-मनन

सोनिया गांधी की Belonging भारतीयता की कसौटी और राजनीतिक विरासत का सवाल

भारत को अपना सर्वस्व सौंपने वाली महिला को क्या जीवनभर अपनी भारतीयता साबित करनी पड़ी? और क्या पारिवारिक संस्मरणों से इतिहास की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं? सोनिया गांधी की पुस्तक Belonging: A Journey of Love इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। पांच सौ से अधिक पृष्ठों के इस संस्मरण पर पूरी तरह चर्चा होने से पहले ही इसके चुनिंदा प्रसंगों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कोई इसे गांधी परिवार के अतीत का खुलासा बता रहा है तो कोई आलोचनाओं को राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित मान रहा है। लेकिन इस पुस्तक का वास्तविक महत्व केवल इसके खुलासों में नहीं, बल्कि इसके शीर्षक 'वक्रद्यश्ठुद्वद्ठुद्व' यानी अपनत्व और स्वीकार्यता के भाव में भी छिपा है। राजीव गांधी से विवाह के बाद सोनिया गांधी ने भारत को अपना घर, परिवार और कर्मभूमि बनाया। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपनाया तथा अंततः देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद उनके विदेशी मूल को लेकर दशकों तक सवाल उठते रहे। प्रधानमंत्री बनने की संभावना के समय यह विवाद इतना बढ़ा कि शरद पवार ने भी इसी मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। सोनिया गांधी ने अंततः प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया और डॉ. मनमोहन सिंह को आगे किया। उनके इस निर्णय को राजनीतिक त्याग या रणनीतिक समझ, दोनों रूपों में देखा जा सकता है। लेकिन पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष 1975 का आपातकाल है। सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के फैसले को राजनीतिक गलती माना है और संजय गांधी की भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित किया है। सवाल यह है कि क्या आपातकाल की जिम्मेदारी संजय गांधी पर केंद्रित करके इंदिरा गांधी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जवाबदेही कम की जा सकती है? 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने का निर्णय इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया था। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, नागरिक अधिकारों का हनन और जबरन नसबंदी जैसी घटनाएं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर गहरे दाग हैं। संजय गांधी की भूमिका विवादास्पद थी, लेकिन इसके लिए पूरी व्यवस्था और तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सोनिया गांधी के संस्मरण को न तो राजनीतिक दुर्भावना से खारिज करना उचित है और न ही उसमें लिखी प्रत्येक बात को अंतिम ऐतिहासिक सत्य मान लेना। संस्मरण व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन तथ्यों और प्रमाणों से होता है। मीडिया को भी सनसनीखेज शीर्षकों के बजाय पुस्तक की समग्रता पर चर्चा करनी चाहिए। Belonging एक तरफ सोनिया गांधी के अपनत्व और स्वीकार्यता के संघर्ष की कहानी है, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत और जवाबदेही पर विचार करने का अवसर भी। भारतीयता जन्मस्थान से बड़ी है, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारी पारिवारिक स्मृतियों से छोटी नहीं हो सकती। लोकतंत्र में सम्मान और जवाबदेही, दोनों समान रूप से जरूरी हैं।

कड़वे वचन



किसी ने पूछाः मंदिर जाते हैं तो पहले घंटीक्यों बजाते हैं? मैंने प्रतिप्रश्न कियाः फोन आता है तो पहले घंटी क्येां बजती है? फोन की घंटी इशारा है कि किसी ने पुकारा है और मंदिर की घंटी भी इशारा है कि प्रभु तेरा ही सहारा है। मंदिर की घंटी के संग मन मंदिर की घंटी भी बजनी चाहिए। कहें- हे प्रभु मेरा नाथ तू है, दुनिया में हूं अकेला, पर मरे साथ तू है।

आज का राशिफल



ज्योतिषाचार्य पंडित लोकेश व्यास

पंचांगः-13 नवम्बर, 2026
दिन-शुक्रवार, अश्विन शुक्ल 10
विक्रम संवत 2083

मेष चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ

बिना मांगे सलाह देने से बचे लेनदेन के मामले में सतर्क रहें देवी पार्वती का पूजन करें

वृष इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो

घर के बाहर वाद-विवाद से दूर रहे मन की इच्छा पूर्ण होगी चांदी की गिलास में पानी पिए

मिथुन का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह

उधार लेने व देने से बचें विद्यार्थियों के लिए समय ठीक नहीं है मन में भटकाव रहेगा वट वृक्ष का पूजन करें

कर्क ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो

ं रुका हुआ पुराना काम बन सकता है परिवार के किसी सदस्य के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ओम विधि रूपाय नमः का जाप करें

सिंह मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे

वरिष्ठ ओं का मार्गदर्शन मिलेगा अपने ऊपर फोकस बनाए रखें भगवान शिव को जल चढ़ाएं

कन्या ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो

कारोबारी कार्य में मन लगेगा लाभ के अवसर मिलेंगे लालच में ना फंसे ओम नमः पार्वती पति यह नमः का जाप करें

तुला रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते

धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे पारिवारिक चिंता रहेगी शुक्र ग्रह का पूजन करें

वृश्चिक ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे

मन प्रफुल्लित रहेगा तेज ड्राइविंग से बचे हनुमानजी के दर्शन करे

धनु ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे

आज मनमाफिक काम होंगे पुरानी स्मृतियों का मन पर कब्जा रहेगा ब्राह्मणों को दान दे

मकर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी

घूमने फिरने की योजना साकार होगी मनचाहे लोगों का साथ मिलेगा हाइपर होने से बचे शनि का पूजन करें

कुंभ गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा

दिन तनाव भरा कठिन रहेगा शाम की बात मन प्रसन्न रहेगा पीपल के वृक्ष में दिया लगाएं

मीन दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची

लोगों के मैसेज पढ़ कर मन प्रसन्न होगा तारीफ होगी लालच में ना फंसे गुरुओं की सेवा करें

महाराष्ट्र में सूखे की मार झेलता किसान, आखिर कब बदलेगी खेती की तस्वीर?

जल संकट, अनिश्चित मानसून, घटता भूजल, खेती की बढ़ती लागत और सरकारी नीतियों की चुनौतियों के बीच महाराष्ट्र का किसान आखिर कब तक सूखे से लड़ता रहेगा? महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में शामिल है, जिनकी पहचान औद्योगिक विकास, व्यापार, वित्तीय गतिविधियों और कृषि उत्पादन के लिए रही है। मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, पुणे आईटी और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बन चुका है तथा राज्य के अनेक जिलों में कृषि और सहकारी संस्थाओं का व्यापक नेटवर्क है। इसके बावजूद महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहां किसान कभी कम बारिश तो कभी बेमौसम बारिश, कभी जलाशयों में पानी की कमी तो कभी फसल की लागत और बाजार भाव की मार झेलने को मजबूर है। सवाल यह है कि आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले महाराष्ट्र का किसान आज भी पानी के लिए आसमान की ओर क्यों देख रहा है?

महाराष्ट्र में सूखे की समस्या केवल एक साल की मौसमी परेशानी नहीं है, बल्कि यह वर्षों से चली आ रही संरचनात्मक समस्या है। राज्य के मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से बार-बार पानी की कमी का सामना करते हैं। हर साल मानसून से उम्मीदें जुड़ती हैं, लेकिन बारिश का असमान वितरण किसानों की मुश्किलें बढ़ा देता है। कहीं सामान्य से कम बारिश होती है तो कहीं कुछ ही दिनों में इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि खेतों की मिट्टी और खड़ी फसल दोनों को नुकसान पहुंचता है। यानी किसान के सामने संकट केवल बारिश की कमी का नहीं, बल्कि बारिश के अनिश्चित और असंतुलित स्वरूप का भी है।

महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस संकट को गंभीर बनाती हैं। सरकारी जल संसाधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रभावित है। राज्य में वर्षा का वितरण 400 से 6,000 मिलीमीटर तक अलग-अलग है और अधिकांश बारिश जून से सितंबर के चार महीनों में होती है। मराठवाड़ा का बड़ा हिस्सा वर्षा छाया क्षेत्र में आता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 600 मिलीमीटर है। यहां बारिश की अनिश्चितता भी अधिक है।

इसके साथ भूजल की समस्या भी कम गंभीर नहीं है। महाराष्ट्र के भूजल सर्वेक्षण एवं विकास तंत्र के अनुसार राज्य के लगभग 91 प्रतिशत भूभाग में कठोर चट्टानी संरचना है। ऐसी चट्टानों में भूजल का संचय और प्रवाह आसान नहीं होता। परिणामस्वरूप बारिश कम होने पर कुएं और बोरवेल तेजी से सूखने लगते हैं। किसान सिंचाई के लिए निजी बोरवेल पर निर्भर होता है और पानी की तलाश में अधिक गहराई तक खुदाई करवाता है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती जाती है। लेकिन केवल प्राकृतिक परिस्थितियों को दोष देकर सरकारी व्यवस्था और कृषि नियोजन की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में दशकों से सूखे की समस्या मौजूद है। इसके बावजूद आज भी बड़ी संख्या में किसान मानसून आधारित खेती करने को विवश हैं। यदि हर साल सूखे की आशंका रहती है तो फिर जल संरक्षण, सिंचाई के वैकल्पिक साधन और फसल विविधीकरण को कृषि नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया?

महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग का बड़ा आर्थिक महत्व है। पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने की खेती ने सहकारी चीनी मिलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। लेकिन गन्ना अधिक पानी मांगने वाली फसल है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता सीमित है, वहां बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गन्ने की खेती बंद कर दी जाए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल है।

मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन और कम पानी में तैयार होने वाली दूसरी फसलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसानों को केवल फसल बदलने की सलाह देना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें बीज, तकनीकी मार्गदर्शन, बाजार की गारंटी, उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की व्यवस्था भी उपलब्ध करानी होगी। जब तक किसान को वैकल्पिक फसल से उसकी लागत और मेहनत का उचित मूल्य मिलने का भरोसा नहीं होगा, तब तक फसल विविधीकरण का लक्ष्य केवल सरकारी कागजों तक सीमित रह सकता है। दूसरी ओर, खेतों में पानी रोकने की व्यवस्था पर भी गंभीरता से काम करना होगा। खेत तालाब, चेक डैम, छोटे बांध, नालों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे उपायों को गांव स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। जलयुक्त शिवार जैसी योजनाओं के अनुभवों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। यह देखना जरूरी है कि जिन गांवों में जल संरक्षण के काम हुए, वहां वास्तव में भूजल स्तर और सिंचाई की स्थिति में कितना सुधार आया।

यहां एक महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आता है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में है। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 7.9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, जबकि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत आंकी गई है। यानी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य की आर्थिक प्रगति का लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। मुंबई में शेयर बाजार की तेजी, पुणे में औद्योगिक विस्तार, नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो और बड़े निवेश राज्य की आर्थिक उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन इनसे उस किसान की समस्या अपने आप हल नहीं होती, जिसकी सोयाबीन की फसल बारिश न होने से सूख गई हो या जिसकी कपास की फसल लागत भी नहीं निकाल पा रही हो।

2026 के मानसून ने इस अंतर को और उजागर किया। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक महाराष्ट्र में सामान्य 970.9 मिलीमीटर के मुकाबले 798.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो लगभग 18 प्रतिशत कम थी। मराठवाड़ा में बारिश की कमी 38 प्रतिशत और विदर्भ में लगभग 27 प्रतिशत तक पहुंच गई। सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण 265 तहसीलों में राहत संबंधी कदमों की आवश्यकता सामने आई। यह आंकड़े बताते हैं कि संकट किसी एक गांव या जिले तक सीमित नहीं रहा।

महाराष्ट्र में जल संरक्षण और सिंचाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, सूक्ष्म सिंचाई और जलग्रहण विकास जैसी पहलों का उद्देश्य किसानों तक पानी पहुंचाना और खेती को मानसून की निर्भरता से मुक्त करना है। इसके बावजूद सवाल यह है कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों तक कितना पहुंचा है?

मराठवाड़ा में 11 बड़े बांधों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़कर जल ग्रिड विकसित करने की योजना भी सामने आई है। यह पहल पानी की क्षेत्रीय असमानता कम करने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसके लिए समयबद्ध क्रियान्वयन, पर्याप्त बजट और पारदर्शिता जरूरी है। केवल योजनाओं की घोषणा से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा।

एक और महत्वपूर्ण पहलू जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी है। गांवों में पानी के उपयोग का हिसाब होना चाहिए। तालाबों और जलाशयों पर अतिक्रमण रोकना, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना तथा भूजल के अनियंत्रित दोहन पर नियंत्रण जरूरी है। सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को छोटे किसानों के लिए सस्ता और सुलभ बनाया जाना चाहिए। साथ ही, पानी के उपयोग में कृषि, उद्योग और शहरी जरूरतों के बीच संतुलन भी स्थापित करना होगा।

सूखे की सबसे बड़ी मार छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ती है। फसल बर्बाद होने के बाद किसान के सामने केवल अगली फसल बोने का सवाल नहीं होता, बल्कि परिवार का खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पुराने कर्ज की अदायगी जैसी जिम्मेदारियां भी खड़ी हो जाती हैं। कई बार किसान कर्ज लेकर दोबारा खेती करता है और अगला मानसून भी साथ नहीं देता। इस तरह प्राकृतिक आपदा धीरे-धीरे आर्थिक संकट और ग्रामीण पलायन का कारण बन जाती है।

ऐसे में फसल बीमा योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना होगा। नुकसान का आकलन समय पर हो और मुआवजा सीधे प्रभावित किसान तक पहुंचे। बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सूखा प्रभावित किसानों को ब्याज राहत, कृषि ऋण पुनर्गठन, पशुओं के लिए चारा और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

जलवायु परिवर्तन ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती और कभी कुछ घंटों में इतनी तेज बारिश हो जाती है कि खेतों में पानी भर जाता है। इसलिए कृषि को केवल पारंपरिक मानसून कैलेंडर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मौसम पूर्वानुमान, स्थानीय स्तर पर कृषि सलाह, सूखा सहन करने वाली बीज किस्में और फसल विविधीकरण को व्यापक स्तर पर अपनाना होगा।

महाराष्ट्र को देश के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। यहां बड़े उद्योग हैं, मजबूत शहरी अर्थव्यवस्था है, व्यापारिक गतिविधियां हैं और निवेश की संभावनाएं भी हैं। लेकिन किसी राज्य की समृद्धि का वास्तविक आकलन केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद, उद्योगों और बड़े निर्माण कार्यों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना होगा कि उस राज्य का किसान कितना सुरक्षित है, ग्रामीण परिवारों की आय कितनी बढ़ी है और खेती प्राकृतिक आपदाओं के सामने कितनी मजबूत हुई है।

(लेखक- सौरभ वार्ष्णेय)

छठ पूजा : आस्था समर्पण और लोक संस्कृति का महापर्व

सूरत में छठव्रतियों के स्वागत के लिए सजे घाट प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का उत्सव छठ पूजा भारत की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और लोक आस्था का ऐसा अनुपम पर्व है, जिसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सूर्य उपासना, अनुशासन, पवित्रता और पारिवारिक सुख-समृद्धि की कामना एक साथ दिखाई देती है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस जीवनदृष्टि का प्रतीक है, जिसमें सूर्य को जीवन का आधार और जल को प्रकृति का अमूल्य उपहार माना गया है। देश के लगभग हर राज्य में छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है। हालांकि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी विशेष परंपरा रही है, लेकिन आज यह पर्व देश की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। गुजरात में भी विशेषकर उत्तर गुजरात के प्रवासी समाज के बीच छठ पूजा का विशिष्ट स्थान है।

छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता छठव्रतियों का कठोर अनुशासन, अटूट विश्वास और अद्भुत समर्पण है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व नहाय-खाय से आरंभ होता है। इसके बाद खरना का विधान होता है। तीसरे दिन व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। इस दौरान व्रती पूरी श्रद्धा, पवित्रता और नियमों का पालन करते हैं। कई श्रद्धालु निर्जला उपवास रखकर सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करते हैं। उनकी यह साधना भारतीय नारी शक्ति, मातृत्व, त्याग और आत्मबल का प्रेरणादायक उदाहरण है। परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और समाज के कल्याण की भावना इस पर्व को और भी विशिष्ट बनाती है।

सूरत जैसे औद्योगिक महानगर में छठ पूजा का उत्साह देखते ही बनता है। वस्त्र उद्योग, हीरा उद्योग, व्यापार, निर्माण क्षेत्र और विभिन्न रोजगारों से जुड़े बिहार, झारखंड तथा पूर्वांचल के लाखों लोग सूरत में रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में श्रमिक और व्यवसायी परिवार छठ पूजा मनाने के लिए अपने वतन लौटते हैं। त्योहार के अवसर पर रेलगाड़ियों और बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। अपने गांव, परिवार और पुश्तैनी परंपराओं के बीच छठ मनाने की इच्छा उन्हें हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है। उनके लिए छठ पूजा केवल त्योहार नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और पारिवारिक जड़ों से जुड़ने का अवसर है।

हालांकि सभी लोग अपने गृह प्रदेश नहीं जा पाते। रोजगार, कारोबार और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अनेक परिवार गुजरात में ही रहकर छठ पूजा मनाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए सूरत में विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा के घाट सजाए जा रहे हैं। बिहार विकास परिषद हर वर्ष छठव्रतियों के लिए घाटों की व्यवस्था करती है। परिषद के कार्यकर्ता श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूजा स्थलों को तैयार करने में जुटते हैं। घाटों की सजावट, साफ-सफाई और धार्मिक आयोजन की व्यवस्थाएं इस बात का प्रमाण हैं कि प्रवासी



समाज ने अपनी संस्कृति को नई भूमि पर भी पूरी जीवंतता के साथ सुरक्षित रखा है। गुजरात की धरती पर छठ का यह आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का सुंदर उदाहरण बन गया है।

छठ पूजा की सफलता में प्रशासन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरत महानगरपालिका, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा सुविधाओं की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। घाटों की समय रहते सफाई, जलाशयों के आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग सुविधाएं, अस्थायी शौचालय, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। जलाशयों में उतरने के लिए सुरक्षित व्यवस्था, फिसलन रोकने के उपाय, बैरिकेडिंग और गहरे पानी वाले स्थानों पर चेतावनी संकेत भी लगाए जाने चाहिए।

संध्या अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था सुचारु रखना पुलिस प्रशासन की विशेष जिम्मेदारी है। भीड़ नियंत्रण, वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग, महिला सुरक्षा और स्वयंसेवकों की तैनाती से श्रद्धालुओं को परेशानी से बचाया जा सकता है। प्रशासन को आयोजक संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी श्रद्धालु को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। साथ ही प्लास्टिक और कचरे से जलाशयों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। प्रशासन की तैयारियों का वास्तविक मूल्यांकन इसी बात से होगा कि छठव्रती कितनी सहजता, सुरक्षित वातावरण और सम्मान के साथ पूजा संपन्न कर पाते हैं।

बिहार विकास परिषद जैसी संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। सामाजिक संस्थाएं जब अपने स्तर पर घाटों की व्यवस्था करती हैं तो प्रशासन का सहयोग भी अधिक प्रभावी बनता है। छठ पूजा किसी एक प्रदेश या भाषा के लोगों का पर्व नहीं रह गया है। इसमें गुजरात के स्थानीय नागरिक भी सहभागी बनते हैं। यही भारत की सांस्कृतिक विविधता की सबसे बड़ी ताकत है। अलग-अलग भाषाएं, वेशभूषाएं और परंपराएं होने के बावजूद आस्था और मानवीय संवेदना सभी को एक सूत्र में बांधती हैं।

आज आवश्यकता है कि छठ पूजा को केवल धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में भी देखा जाए। सूर्य और जल की उपासना हमें प्रकृति के महत्व का संदेश देती है। स्वच्छ घाट, निर्मल जल और अनुशासित आयोजन ही इस पर्व की वास्तविक गरिमा को बनाए रख सकते हैं। सूरत में सजते छठ पूजा के घाट इस बात के प्रतीक हैं कि इंसान रोजगार के लिए अपना घर छोड़ सकता है, लेकिन अपनी संस्कृति और संस्कारों को नहीं छोड़ता। हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी छठव्रती उसी श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जिस श्रद्धा से वे अपने गांव में करते आए हैं। उनकी आस्था, तपस्या और समर्पण को नमन करना चाहिए। प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों के सामूहिक सहयोग से यह महापर्व सूरत में भी हर्षोल्लास, शांति और गरिमा के साथ संपन्न हो, यही कामना है।

छठ पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था के लिए स्थान की दूरी बाधा नहीं बनती। जहां श्रद्धा है, वहीं संस्कृति है और जहां संस्कृति है, वहीं भारत की आत्मा जीवित है।

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

विश्व बैंक के ताजा आंकलन के अनुसार भारत में घट रही है गरीबी

विश्व बैंक के ताजा आंकलन के अनुसार भारत में घट रही है गरीबी हाल ही में विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन जारी कर बताया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या तेजी से घट रही है। केंद्र सरकार की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य श्रीमती शमिका रवि ने भी अपने एक रिसर्च पेपर में बताया है कि भारत में 10 वर्ष पूर्व तक गरीबी आंकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता था। इन सिफारिशों के अनुसार भारतीय नागरिकों को पूर्व निर्धारित स्तर तक कैलोरी प्राप्त करने हेतु होने वाले खर्च से यदि अधिक आय है तो उसे गरीबी की रेखा से ऊपर मान लिया जाता था। कैलोरी की आवश्यकता शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में निवासरत नागरिकों के लिए अलग अलग स्तर पर तय की जाती थी, इसे खाद्य गरीबी की संज्ञा भी दी जाती थी। इसके बाद, रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर गरीबी का आंकलन किया जाने लगा, जिसमें खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि को जोड़ा गया है। भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, देश की कुल जनसंख्या का, 29.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है। यह एक अतुलनीय उपलब्धि मानी जा रही है। पूरे भारत वर्ष में ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में कमी दृष्टिगोचर हुई है। विश्व बैंक के ही एक अन्य अनुमान के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या, (अर्थात 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की आय वाले नागरिक) वर्ष 2011 में 27 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत हो गई है। जबकि, 4.2 अमेरिकी डॉलर तक की प्रतिदिन आय वाले नागरिकों की संख्या वर्ष 2011 के 57.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 16.1 प्रतिशत रह गई है, जिसके वर्ष 2026 में 14.2 प्रतिशत एवं वर्ष 2028 में 12.1 प्रतिशत तक नीचे रहने का अनुमान विश्व बैंक द्वारा लगाया गया है।भारत में निवासरत समस्त वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित, के नागरिकों की गरीबी में कमी दिखाई दी है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में निवासरत अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों की गरीबी तेजी से घटी है। लगभग12 वर्ष पूर्व तक जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के बीच गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या 50 प्रतिशत तक थी जो अब घटकर 12 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गई है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में यदि इतनी कमी आई है तो फिर गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 85 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी गरीब वर्ग की सहायता के लिए विशेष योजनाएं क्यों चलाई जा रही है। इस प्रश्न के उत्तर में यह तर्क दिया जा रहा है कि उक्त योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इससे गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री पर कम खर्च करना पड़ रहा है और इस मद से हुई बचत को गरीब वर्ग अपने सामाजिक स्तर में सुधार पर खर्च करने लगा है। भारत में हाल ही के समय में गरीब वर्ग की खाद्य सामग्री में फल, दूध, पनीर, दूध से बने अन्य पदार्थ, अंडे, आदि भी शामिल हो गए हैं। इससे गरीब वर्ग के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। इसके साथ ही, पूर्व में केंद्र सरकार को भारी मात्रा में अन्न का स्टॉक रखना पड़ता था। अन्न के स्टॉक को, बहुत बड़ी मात्रा में, चूहे नुक्सान पहुंचाते थे एवं वर्षा ऋतु में भी अन्न का भारी मात्रा में नुक्सान होता था। अब, चूंकि गेहूं एवं चावल जैसी खाद्य सामग्री को गरीब जनता के बीच सहायता के रूप में बांट दिया जाता है, इससे देश में अन्न की बचत ही हो रही है। केंद्र सरकार के अन्न को स्टोर करने की मद पर भी खर्च बहुत कम हो गया है। आज भारत में गरीब वर्ग भी गेहूं एवं चावल के स्थान पर पोषण सामग्री का अधिक उपयोग कर रहा है। 12 वर्ष पूर्व, भारत में 63 प्रतिशत नागरिकों द्वारा ताजे फलों का सेवन किया जाता था, आज यह संख्या बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। देश में दालों एवं फलों जैसी खाद्य सामग्री का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।देश में बेरोजगारी की दर में भी भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है। भारत में बेरोजगारी की दर अब घटकर 3.1 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। परंतु, विभिन्न राज्यों के बीच बेरोजगारी की दर में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। गुजरात में बेरोजगारी की दर केवल 0.9 प्रतिशत है तो छत्तीसगढ़ में केवल 1.9 प्रतिशत है। परंतु केरल में 12 प्रतिशत है तो हिमाचल प्रदेश में 17 प्रतिशत है। इतना बड़ा अंतर, राज्यों द्वारा निर्धारित की जा रही व्यापार की नीतियों में अंतर के चलते दिखाई दे रहा है।

(लेखक - प्रहलाद सबनानी)

संस्कारधानी की स्वच्छता में ऐतिहासिक छलांग

जबलपुर, यशभारत। स्वच्छता के क्षेत्र में संस्कारधानी जबलपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान रचते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, जिसे महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, तत्कालीन निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार और वर्तमान निगमायुक्त अग्रिम कुमार ने ग्रहण किया। इस सफलता के पीछे कोई एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि ठोस तकनीकी प्रबंधन, वैज्ञानिक कचरा निष्पादन और प्रशासनिक नवाचारों का लंबा सफर है।

22वें से दूसरे स्थान तक का सफर

जब वर्तमान महापौर ने कार्यभार संभाला था, तब स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर देश में 22वें पायदान पर था। वहां से क्रमिक सुधार करते हुए शहर 13वें, फिर पांचवें और अब सीधे दूसरे स्थान पर पहुंचा है। इस सफर की सफलता के पीछे वे तकनीकी और प्रशासनिक बिंदु रहे, जिन्होंने शहर की सूरत बदल दी।

- **वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और वैज्ञानिक कचरा प्रोसेसिंग:** शहर में आधुनिक कचरा प्रबंधन के तहत नवंबर-दिसंबर 2025 में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का संचालन शुरू कराया गया। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के महज तीन महीनों में लगभग 3.5 लाख टन कचरे की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग की गई।
- **डंप साइट्स की मुक्ति और भूमि सुधार:** पुराने कचरे के विशाल ढेरों का निष्पादन कर लगभग 17 एकड़ भूमि को पूरी तरह कचरा मुक्त कराया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला।



- **थ्री-आर (3R) सेंटर्स का अभिनव प्रयोग:** 'रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल' की अवधारणा पर आधारित थ्री-आर सेंटर बनाए गए, जिनमें बुक बैंक, खिलौना बैंक और कपड़ा बैंक जैसी व्यवस्थाओं के जरिए अनुपयोगी वस्तुओं का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया गया।
- **मैदानी मॉनिटरिंग और नाइट स्वीपिंग:** व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए निगमायुक्त द्वारा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से मैदानी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा, प्रमुख व्यस्त मार्गों पर रात्रिकालीन सफाई (नाइट स्वीपिंग) को प्रभावी बनाया गया।
- कड़े नियम और प्रवर्तन : सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर निरंतर 'स्पॉट फाइन' की कार्रवाई की गई तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए लगातार जब्ती अभियान चलाए गए।

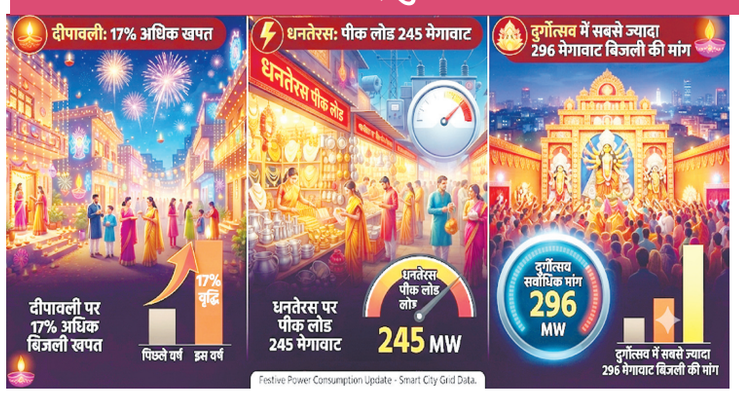
डुमना में स्वागत और अब 'नंबर वन' की तैयारी

जबलपुर के राष्ट्रीय पटल पर चमकने और दूसरा स्थान हासिल करने के बाद संस्कारधानी लौटने पर महापौर, निगमायुक्तों और सफाई मित्रों का शहर में अभूतपूर्व और जोरदार स्वागत किया गया। नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने फूल-मालाओं से इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाया। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने यह पुरस्कार शहर के प्रत्येक देवतुल्य नागरिकों और सफाई मित्रों को समर्पित किया। साथ ही, स्पष्ट किया कि यह सम्मान केवल एक पड़ाव है, और अब जबलपुर का अगला लक्ष्य देश में 'नंबर वन' बनने का है। शहरवासियों और सफाई मित्रों के इस जोश से यह तय है कि संस्कारधानी स्वच्छता के मामले में नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।

धनतेरस पर सबसे ज्यादा जगमगाया शहर, दीवाली को छोड़ा पीछे

जबलपुर, यशभारत। जबलपुर में बिजली खपत के आंकड़े बताते हैं कि दीवाली से कहीं ज्यादा धन-तेरस के दिन चमक-दमक व सजावट रही। हालाँकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 11 फीसदी ज्यादा बिजली की रोशनी की रही। मजेदार बात तो यह है कि दीवाली एवं धन-तेरस में की गई सजावट दुर्गोत्सव को पीछे नहीं छोड़ पाई।

पिछले साल के मुकाबले दीपावली पर 17 फीसदी अधिक बिजली खपत, धनतेरस पर पीक लोड 245 मेगावाट रहा, दुर्गोत्सव में सबसे ज्यादा 296 मेगावाट बिजली की मांग



सच कहें तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते, यही वजह है कि वे कभी-कभी चौंकाते हैं। मसलन इस बार शहर में बिजली खपत के जो आंकड़े मिले हैं, वे दर्शाते हैं कि धन-तेरस के दिन पीक लोड आवर पर 245 मेगावाट बिजली की खपत हुई। जो इस दीपोत्सव पर सबसे ज्यादा थी। छोटी दीवाली अर्थात रूप-चतुर्दशी के दिन बिजली की खपत घटकर 241 मेगावाट पर आई। इसी प्रकार यह खपत दीवाली के दिन 230 मेगावाट दर्ज हुई, हालाँकि पिछली दीवाली जो 20 अक्टूबर 2025 को थी, तब बिजली की मांग 196 मेगावाट तक ही पहुँची थी। जो पिछले साल से लगभग 17 फीसदी ज्यादा खपत है । उसके पूर्व 2024 में यह खपत 190.3 मेगावाट ही थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि दीवाली की रात दुकानों की सजावट प्रायः खत्म सी हो जाती है, जबकि धन-तेरस के दिन घरों के साथ-साथ दुकानों की साज-सज्जा भी शबाब पर रहती है। जिस कारण दीवाली से कहीं ज्यादा धन-तेरस के दिन ज्यादा मेगावाट बिजली खर्च हुई। वहीं दूसरी ओर नवरात्र के दौरान घर-घर में सजावट भले न हो लेकिन दुर्गा-पंडालों, मंदिरों व सड़कों पर काफी सजावट की जाती है। साथ ही दुकानों पर भी उपभोक्ताओं को लुभाने पर्याप्त साज-सज्जा की जाती है। जिस कारण इस दौरान बिजली की सर्वाधिक खपत 296 मेगावाट (18 अक्टूबर 2026) तक पहुँची थी। प्रदेश स्तर की बिजली खपत पर नजर डाली जाए तो इस दीवाली पर 17 हजार 893 मेगावाट मांग तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष से करीब 43 फीसदी अधिक थी। पिछले वर्ष यह खपत 12 हजार 452 मेगावाट तक पहुँची थी।

दीवाली पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिये चौक-चौकस प्रबंध

इस दीवाली पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो इसके लिये काफी चौकसी बरती गई। एमपी ट्रांसको के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी के अनुसार 1278 ट्रांसमिशन लाइनों और 418 अतिरिक्त हाई टेंशन सब-स्टेशनों से सतत विद्युत आपूर्ति की गई, हर सब-स्टेशनों पर रात्रि में निगरानी हेतु कर्मियों को तैनात किया गया था।

पारे में आंशिक गिरावट, मौसम शुष्क रहने की संभावना

किसानों को सलाह,कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता दें



जबलपुर यश भारत। मौसम में किंचित गिरावट के साथ आगे मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताते हुए कहा कि वर्तमान में फसलों की बुबाई में कम पानी वाली फसलें मसूर चना आदि को प्राथमिकता दें तो अच्छा होगा। ठंड को लेकर कहा गया है कि अभी पारे में किंचित गिरावट आई है। लेकिन आने वाले समय ठंड बढ़ने की संभावना है। अतः बदलते मौसम को देखते हुए अपने खान-पान के साथ गर्म कपड़े पहनें। यद्यपि पाकिस्तान के आसपास और उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती विछोभ है। लेकिन मध्य प्रदेश में उसका कोई असर नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पारा किंचित गिरावट के साथ 12.8 सेल्सियस दर्ज किया गया जो गत दिवस की अपेक्षा.4 कम यानि सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। आद्रता 73 फीसदी रही जबकि गत दिवस आद्रता 62.3 रही यानि आद्रता में 10 फीसदी की वृद्धि आंकी गई। बहरहाल मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव के चलते लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए किसानों को अतिरिक्त सलाह दी है कि वे सरसों,तुरई की बुबाई के साथ रबी फसल के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से खाद उर्वरक आदि का समय रहते इंतजाम कर लें। ताकि फसल का अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ अर्जित कर सकें।

किसना ज्वेलर्स में सनसनीखेज चोरी

पिछले हिस्से की दीवार में सेंध लगाकर घुसे चोर, डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी लेकर रफू-चक्कर





दीवाली की वजह से शो रूम में था करोड़ों का स्टाक

कटनी, यशभारत। माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एलआईसी के पास बरगवां स्थित किसना ज्वेलर्स में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ज्वेलर्स के पिछले हिस्से में दीवार पर सेंध लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया और ज्वेलरी लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने शो रूम के अंदर घुसकर गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किसना ज्वेलर्स में कितने की चोरी हुई है। आज सुबह जब ज्वेलर्स के कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे, तब शो रूम के अंदर का दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने तत्काल ज्वेलर्स संचालक मोहन बजाज को घटना की सूचना दी। उन्होंने इसकी सूचना माधवनगर पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। किसना ज्वेलर्स में वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. कमल मौर्य के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने ज्वेलरी शॉप के अंदर से लेकर पिछले हिस्से का मुआयना किया और जांच पड़ताल की। पुलिस सीसीटीव्ही फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि चोर ज्वेलरी शॉप से कितने का जेवरात ले गए। फिर भी एक आंकलन के अनुसार दुकान से करीब 10 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी चोरी जाने का अनुमान है। वारदात का खुलासा करने के लिए डॉग स्कवाड और फिंगर प्रिंट एक्पर्ट को भी बुलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोरों ने किसना ज्वेलर्स के पिछले हिस्से में दीवार पर सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पुलिस जब यहां पहुंची तो यहां से पाना, पिंचिस और पेंचकस मिले। पुलिस ने इन्हें जब्त किया। अभी इस मामले को लेकर किसी भी पुलिस अधिकारी से बात नहीं हो सकी है।





अग्निकांड के बाद फूटा जनाक्रोश, बंद रहा बरही

व्यापारियों ने नहीं खोले दुकानों के ताले

दोषी अफसरों की जवाबदेही, एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग



बरही/कटनी, यशभारत। दीपावली की रात बरही नगर में हुए हृदयविदारक अग्निकांड में अग्रवाल परिवार के आधा दर्जन सदस्यों की जिंदा जलकर मौत के मामले ने अब जनाक्रोश का रूप ले लिया है। घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी घटना के लिए दोषी जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई ठोस वैधानिक कार्रवाई नहीं होने से नाराज नगरवासियों और व्यापारियों ने आज गुरुवार को बरही बंद का आव्हान किया। बंद के समर्थन में व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों के ताले नहीं खोले। होटल से लेकर मेडिकल स्टोर्स तक बंद रहे और पूरा बरही नगर बंद नजर आया। नगरवासियों एवं व्यापारियों में सरकारी व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। इस दौरान पूरा बरही नगर स्वस्फूर्त बंद रहा। लोगों ने कहा कि घटना के 5 दिन बाद भी प्रशासन जांच के नाम पर पूरे मामले में लीपापोती कर रहा है। जिन अफसरों के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें ही जांच का जिम्मा सौंपा गया है। बरही बंद के दौरान 11 बजे नगर के लोग कमानिया गेट में एकत्रित हुए और जिम्मेदार लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों पर जबाबदेही तय करने की पुरजोर मांग कर रहे है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अग्निकांड के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए। उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सेवा से बर्खास्त करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते प्रशासनिक अमला सक्रिय होता और राहत बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाते तो छह अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सकता था। गौरतलब है कि दीपावली की रात बरही नगर के पूरन अग्रवाल के तीन मंजिला दुकान एवं आवासीय भवन में भीषण आग भड़क उठी थी। इस दर्दनाक हादसे में 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल, उनकी पत्नी चंद्रकला अग्रवाल, बहू सोनम अग्रवाल, दो माह का मासूम अर्विश, 12 वर्षीय आर्या और 6 वर्षीय अन्वी की मौत हो गई थी।

होटल और मेडिकल स्टोर्स भी रहे बंद

गुरुवार सुबह से ही नगर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर नहीं खोले। होटल संचालकों और मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों के बंद रहने से भी नगर में बंद का असर साफ दिखाई दिया। छह लोगों की असमय मौत से आहत नगरवासी अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने को तैयार नहीं हैं। उनकी मांग है कि इस हृदयविदारक हादसे की निष्पक्ष जांच हो। लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को चिह्नित किया जाए और उनके विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए ठोस कार्रवाई की जाए।



9 घंटे तक जिम्मेदारों की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल

हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य के दौरान करीब नौ घंटे तक स्थानीय एवं जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मौके पर बरही थाना के दो कर्मचारी, नगर परिषद के दमकल प्रभारी तीरथ चतुर्वेदी और नगर परिषद अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी नहीं रही।

20 नवंबर को यूपीएससी की बैठक में तय होंगे नाम, 23 से पहले आ सकता है बड़ा फैसला

भोपाल, यशभारत।

मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के चयन को लेकर प्रशासनिक गलियारों में काउंटडाउन शुरू हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस अहम प्रक्रिया के तहत 20 नवंबर को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकबुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के लिए योग्य नामों पर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

बैठक में तय होगी राज्य के अगले मुखिया की तस्वीर

दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई दिग्गज शामिल होंगे। इनमें मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय शुक्लाऔर वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाणा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। यूपीएससी की मुहर लगने के बाद तैयार होने वाले तीन नामों के पैनल में से ही राज्य सरकार किसी एक अनुभवी चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपेगी। इस चयन प्रक्रिया के समीकरणों में एक अहम बदलाव भी देखने को मिला है। शुरुआती सूची में 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल थे, लेकिन विशेष पुलिस महानिदेशक जी. अखोटे द्वारा अपनी दावेदारी वापस लिए जाने के बाद अब मैदान में 11 वरिष्ठ अधिकारी ही बचे हैं। 20 नवंबर को होने वाली बैठक में इन्हीं 11 अधिकारियों की वरिष्ठता, उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड और पात्रता के मानकों पर बारीकी से समीक्षा होगी।

रेस में जिन प्रमुख नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें:

विशेष पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन
प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव
वरुण कपूर
पंकज श्रीवास्तव
आदर्श कटियार
सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, अंतिम मुहर यूपीएससी के पैनल पर ही निर्भर करेगी।

अमिताभ बच्चन की 95 वर्षीय सास इंदिरा भादुड़ी की तबीयत बिगड़ी, भोपाल के पारुल अस्पताल में भर्ती

भोपाल, यशभारत। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की 95 वर्षीय सास और जया बच्चन की माता इंदिरा भादुड़ी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें भोपाल के पारुल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार, उन्हें एलर्जी की शिकायत है। यह परेशानी उन्हें बीच-बीच में सामने आती है, और स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल लाया गया। फिलहाल उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है और डॉक्टर लगातार उनकी रिकवरी पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल से उन्हें कब छुट्टी मिलेगी, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य में सुधार और रिकवरी के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि इंदिरा भादुड़ी का परिवार शहर के श्यामला हिल्स स्थित अंसल अपार्टमेंट में रहता है। इससे पहले फरवरी 2020 में अमिताभ बच्चन अपनी सास का 90वां जन्मदिन मनाने भोपाल आए थे।

करोड़ों की मिठाई का खेल या विभाग की खानापूर्ति ?

रायपुर में 5 सैंपल फेल, फिर भी कार्रवाई सिर्फ दुकानों तक - बड़े कारखानों के पाम आईल, सैक्रिन और अवमानक दूध पाउडर पर चुप्पी

यश भारत

रायपुर. त्योहारीं सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ते ही राजधानी रायपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच में शहर के कई प्रतिष्ठानों से लिए गए मिठाई और खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित या अवमानक पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर इन खाद्य पदार्थों के नमूने त्योहार से पहले लिए गए थे, तो उनकी जांच रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं आई ?

राजधानी के तेलीबांधा क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों की जांच में कलाकंद, खोवा, कुंदा और पेड़ा जैसे खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए। वहीं पचपेड़ी नाका स्थित एक ढाबे से लिया गया पनीर भी जांच में असुरक्षित निकला। एक अन्य प्रतिष्ठान का पनीर अवमानक पाया गया। जबकि सूत्रों के मुताबिक रायपुर के सभी बड़े प्रतिष्ठानों की फैक्ट्रीयों और कारखानों में खुल कर पाम आयल और अवमानक दूध पाउडर का उपयोग खुल कर किया गया है। यह सीधे तौर पर आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि इन बड़े कारखानों और फैक्ट्रीयों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?

शोरूम की मिठाइयों में कॉकरोच ने सफाई व्यवस्था की और चाशनी में फफूंद ने खोली क्वालिटी की पोल

17 अक्टूबर को खाद्य विभाग की टीम ने तेलीबांधा क्षेत्र के तीन मिठाई प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया था। विभागीय कार्रवाई के दौरान चार पतीलों में मरे हुए कॉकरोच पाए जाने और चाशनी में फफूंद मिलने की जानकारी सामने आई है। वहीं पचपेड़ी नाका स्थित रायपुर ढाबा के किचन में गंदगी मिलने के साथ संदिग्ध पनीर भी मिला था। कार्रवाई के दौरान विभाग ने खाद्य लाइसेंस



निलंबित करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों को कम से कम तीन दिन बंद रखने के निर्देश दिए थे।

खानापूर्ति कर मात्र 150 किलो मिठाई को किया नष्ट और 50 किलो संदिग्ध पनीर जब्त

जांच अभियान के दौरान मौके पर करीब 150 किलो मिठाई और 10 किलो पनीर नष्ट कराया गया। इसके अलावा 50 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया था। इसके बाद प्रयोगशाला जांच में भी कई खाद्य पदार्थों के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इससे त्योहारों के दौरान बाजार में बिकने वाली मिठाइयों और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

लैब रिपोर्ट देर से आने पर उठे गंभीर सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खाद्य विभाग ने त्योहार से पहले ही नमूने लिए थे, तो उनकी जांच रिपोर्ट समय रहते क्यों नहीं आई ? यदि रिपोर्ट त्योहार के दौरान ही सामने आ जाती, तो मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की कार्रवाई की जा सकती थी।अब रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

सिर्फ रायपुर नहीं, दूसरे जिलों से भी सामने आए फेल सैंपल

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सिर्फ रायपुर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी नमूने फेल होने की जानकारी सामने आई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 29 सितंबर 2026 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र जारी कर नवरात्रि, दशहरे और दीपावली के दौरान खाद्य पदार्थों की सतत जांच, निगरानी और नमूने लेने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए थे। इसमें दूध एवं दुग्ध उत्पादों, मिठाइयों, नमकीन, खाद्य तेल और घी को विशेष निगरानी में रखने को कहा गया था।

रायपुर सहित प्रदेश भर में सामने आए मामलों ने एक तरफ खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता और गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी तरफ नमूने लेने से लेकर जांच रिपोर्ट आने और कार्रवाई होने तक की पूरी प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है।

अब देखना होगा कि विभाग आगे सिर्फ संबंधित दुकानों पर कार्रवाई तक सीमित रहता है और त्यौहारों के दौरान और त्यौहारों पहले बड़े पैमाने पर मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाता है और बड़े खिलाड़ियों की फैक्ट्रीयों और कारखानों में भी पहुंचता है या सिर्फ आगे भी सिर्फ खानापूर्ति चलती रहेगी ?



- धमतरी में झलक ब्रांड हल्दी पाउडर अवमानक पाया गया।
- कोरबा में सिल्वर क्राईन ब्रांड मैदा मानकों पर खरा नहीं उतरा।
- बीजापुर में मां भगवती ब्रांड पोहा अवमानक मिला।
- राजनांदगांव में खुली शक्कर और उड़द दाल के नमूने भी निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे।

त्योहारों में जांच अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल ?

त्योहारों के दौरान खाद्य विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ सैंपल लेने तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि जिन खाद्य पदार्थों की बिक्री बड़ी मात्रा में होती है, उनकी जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था कितनी प्रभावी रहीं ?

छठ पर्व को लेकर दुर्ग निगम अलर्ट, महापौर ने तालाबों और घाटों की सफाई तेज करने के दिए निर्देश



यश भारत

दुर्ग। छठ महापर्व को देखते हुए नगर पालिक निगम दुर्ग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महापौर अलका बाघमार ने बुधवार को वार्ड क्रमांक 29 स्थित सिविल लाइन शीतला तालाब और वार्ड क्रमांक 50 के बोरसी तालाब सहित विभिन्न तालाबों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रमुख तालाबों और छठ घाटों में युद्धस्तर पर प्रतिदिन सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि छठ पर्व से पहले घाटों की सफाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित सफाई कर्मचारियों के साथ मशीनों की मदद से जलकुंभी, प्लास्टिक, तैरता कचरा और अपशिष्ट हटाया जा रहा है। घाटों की सीढ़ियों और किनारों की भी विशेष सफाई कराई जा रही है।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग प्रभारी निलेश अग्रवाल, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकर, ज्ञानदास बंजारे, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता सहित निगम की टीम मौजूद रही।

महापौर अलका बाघमार ने नागरिकों से भी अपील की कि वे तालाबों और घाटों में कचरा, प्लास्टिक एवं पूजन सामग्री इधर-उधर न फेंकें और छठ पर्व के दौरान स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें।

भिलाई इस्पात संयंत्र की कोमल मेहरा को ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड-2026

यश भारत

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के परियोजना-वाणिज्यिक विभाग में कार्यरत सहायक महाप्रबंधक सुश्री कोमल मेहरा ने अपनी उपलब्धियों से संयंत्र का गौरव बढ़ाया है। उन्हें ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स-2026 के तहत 'एक्सीलेंस इन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स-2026 में ग्लोबल ट्रायम्फ फाउंडेशन द्वारा उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।

सुश्री मेहरा सेल में अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इससे पहले उन्हें एसएचआरएम बेस्ट लर्नर अवार्ड और महिला दिवस-2026 पर बेस्ट लर्निंग एम्बेसडर के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।

उन्होंने अधिकारियों की पदोन्नति परीक्षा की तैयारी के लिए व्यावसायिक संचार और परिवर्तन प्रबंधन विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। साथ ही ई-1 से ई-6 स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए हैं।

वर्ष 2008 में सेल से जुड़ीं कोमल मेहरा वर्तमान में परियोजना प्रबंधन, निविदा एवं अनुबंध प्रबंधन और क्रय संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि को





भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

30 नवंबर तक संपत्तिकर जमा करने पर मिलेगी 2 प्रतिशत की छूट

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्तिकरदाताओं को राहत देते हुए 30 नवंबर 2026 तक एकमुश्त संपत्तिकर जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। निगम प्रशासन ने भवन एवं भूमि स्वामियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। निगम के अनुसार, संपत्ति स्वामियों को अपनी संपत्ति की सही जानकारी स्व-विवरणी में दर्ज करना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान गलत जानकारी पाए जाने पर नियमानुसार पांच गुना शास्ति अधिरोपित की जाएगी। वहीं, बिना अधिभार के स्व-विवरणी जमा करने और बकाया राशि भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से समय पर संपत्तिकर जमा कर अनावश्यक कार्रवाई से बचने की अपील की है। ऑनलाइन भुगतान एवं अधिक जानकारी के लिए निगम के पोर्टल *https://chhattishgarhmunicipal.com* या हेल्पलाइन एवं व्हाट्सएप नंबर 9153986401 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 15 हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नगर पालिक निगम भिलाई ने आबादी भूमि पर निवासरत 15 हितग्राहियों की अंतिम पात्रता सूची प्रकाशित कर दी है। लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत आवेदनों की जांच और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सूची जारी की गई है। जारी सूची के अनुसार, वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी-खम्हरिया से 8 हितग्राहियों को पात्र पाया गया है। इनमें प्रेम लाल महार, बुधु राम सोनवानी, नरेन्द्र कुमार देवांगन, शशि कुमार सेन, बल्लू बंजारे, ललिता साह, बुध राम सोनवानी और कन्हैया लाल निर्मलकर शामिल हैं। वहीं, वार्ड क्रमांक 22 कुरूद से 7 हितग्राहियों का चयन किया गया है। इनमें दुरपति साहू, कृष्णा देवांगन, रामकुंवर देवांगन, बालराम देवांगन, कांति बाई देवांगन, महेन्द्र कुमार साहू और कुंभकरण शामिल हैं। निगम प्रशासन के अनुसार, सभी आवेदनों का निर्धारित पात्रता मापदंडों और दस्तावेजों के आधार पर परीक्षण किया गया है। दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की गई है। अब पात्र हितग्राहियों को शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार आवास निर्माण का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है।

दुर्ग जिले में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, 11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 18 वर्ष के युवाओं को नाम जुड़वाने का मौका

दुर्ग। जिले में निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 12 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत मतदाता 11 दिसंबर 2026 तक अपना नाम जुड़वाने, कटवाने और सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक और प्रेसवार्ता



लेकर पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर को कर दिया गया है। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा।

नाम जोड़ने और संशोधन के लिए अलग-अलग फॉर्म

- फॉर्म-6 -नया नाम जुड़वाने के लिए।
- फॉर्म-7 -मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए।
- फॉर्म-8 -नाम, पता सहित अन्य प्रविष्टियों में सुधार और विधानसभा क्षेत्र के भीतर स्थानांतरण के लिए।

जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों के आधार पर भी नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की सुविधा रहेगी।

जिले में 12.63 लाख से अधिक मतदाता

प्रारंभिक मतदाता सूची के अनुसार जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों सहित साजा और बेमेतरा विधानसभा के आंशिक क्षेत्रों को मिलाकर कुल 12 लाख 63 हजार 157 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 6 लाख 28 हजार 280 पुरुष, 6 लाख 34 हजार 836 महिला और 41 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। जिले में पुरुषों की तुलना में 6,556 महिला मतदाता अधिक हैं। कुल 1,742 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन और संशोधन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य-//1शह्लद्गह्वह्य.द्गष्ठ्र.द्श1.द्ब ठ्ठ तथा ड्डश्शह्लद्गह्वः ॥द्गद्यश्चद्यद्बठ्ठद्बद्ब श्चश्च के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतदाता इसी पोर्टल पर अपना नाम भी खोज सकते हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों के दौरान आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

मतदाता सूची से संबंधित जानकारी और शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तारीखें

- प्रक्रिया निर्धारित तिथि
- प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026
- दावा-आपत्ति 12 नवंबर से 11 दिसंबर
- दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर
- अंतिम मतदाता सूची4 जनवरी 2027

दुर्ग जिले में 795 हेक्टेयर धान फसल पर पेनिकल माइट का आंशिक प्रकोप, कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी

दुर्ग। जिले में धान की फसल पर पेनिकल माइट कीट का प्रकोप कुछ सीमित क्षेत्रों में देखा गया है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में धान की कुल बोआई लगभग 1.34 लाख हेक्टेयर में हुई है, जिसमें करीब 795 हेक्टेयर क्षेत्र में इस कीट का आंशिक प्रभाव सामने आया है। विभाग ने स्थिति को सामान्य बताते हुए किसानों को फसल की नियमित निगरानी करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के वैज्ञानिकों के अनुसार पेनिकल माइट एक सूक्ष्म कीट है, जो धान के गभोट और बालियों के दानों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है।

इसके प्रकोप से पत्तियों पर सफेद-भूरे धब्बे, बालियों पर काले निशान और दानों का सिकुड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे दानों का विकास प्रभावित होने के साथ बालियां खाली रह सकती हैं। कृषि विभाग ने किसानों को खेतों में यूरिया का अनावश्यक उपयोग नहीं करने, खरपतवार हटाने और कृषि यंत्रों की सफाई रखने की सलाह दी है। कीट के लक्षण दिखाई देने पर प्रति एकड़ 150 मिलीलीटर स्पायरोमेसिफेन 22.9 प्रतिशत एससी तथा 150 मिलीलीटर प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत ईसी का अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करने की सलाह दी गई है। उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि फसल में कीट-व्याधि के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल कृषि विभाग के मैदानी अमले या कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से संपर्क करें, ताकि समय रहते उचित नियंत्रण किया जा सके।

छठ पूजा से पहले तालाबों की सफाई पर निगम का जोर, कमिश्नर ने किया निरीक्षण

भिलाई। दीपावली पर्व के समापन के साथ ही छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भिलाई-चरौदा नगर निगम प्रशासन ने छठ पूजा को देखते हुए तालाबों की साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। निगम आयुक्त श्री एसके सुंदरानी ने क्षेत्र के प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आयुक्त सुंदरानी ने निगम क्षेत्र के गतवा तालाब, बोधवा तालाब, उमदा छठ तालाब सहित दादर और डबरापारा स्थित तालाबों का अवलोकन किया। उन्होंने तालाबों के आसपास की स्वच्छता, पूजा स्थल की स्थिति और छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ पूजा से पहले सभी प्रमुख तालाबों की समुचित सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु तालाबों में पहुंचते हैं। इसे देखते हुए निगम प्रशासन ने सफाई के साथ



ही घाटों और आसपास के क्षेत्रों को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया है। आयुक्त ने सफाई व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने तथा निर्धारित समय से पहले सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्वच्छता प्रभारी बीनू वर्मा, पीआर विनय वर्मा, ताम्रध्वज साहू सहित निगम के सफाई विभाग का अमला मौजूद रहा।

दुर्गम रास्तों और तालपेरू नदी को ट्रैक्टर से पार कर सुदूर गांवों में पहुंचे कलेक्टर विश्वदीप, ग्रामीणों की समस्याओं से हुए रूबरू

डोंडीतुमनार, गमपुर और पीड़िया में लगी प्रशासन की जनचौपाल, ग्रामीणों से सीधा संवाद कर जानी जमीनी हकीकत

गमपुर में रात के अंधेरे में भी लगी जनचौपाल, ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निराकरण के दिए निर्देश

बीजापुर। जिले के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने और ग्रामीणों की समस्याओं का प्रत्यक्ष निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर विश्वदीप एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे ने ग्राम पंचायत डोंडीतुमनार, गमपुर एवं पीड़िया का दौरा कर जनचौपाल लगाई। इस दौरान अधिकारियों ने दुर्गम रास्तों और तालपेरू नदी को ट्रैक्टर से पार कर दूरस्थ गांवों तक पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। वहीं गमपुर में रात्रि के समय भी जनचौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं और आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना।

कलेक्टर विश्वदीप ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं,

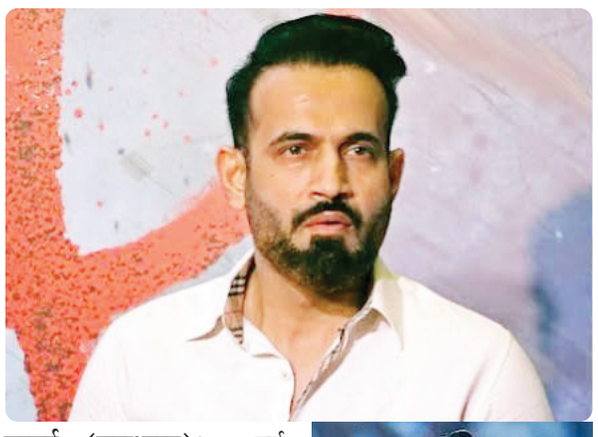


आवश्यकताओं एवं गांवों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ अंतिम छोर पर बसे प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, पुल-पुलिया, विद्युत व्यवस्था, बाजार व्यवस्था सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं एवं मांगें रखीं। कलेक्टर श्री विश्वदीप ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा, पेयजल की उपलब्धता, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। साथ ही ग्रामीणों की मांगों के अनुरूप आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

अर्शदीप के आने से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी मजबूत हुई : इरफान पठान





मुम्बई (यशभारत)। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के आने से मुम्बई इंडियंस टीम और भी मजबूत हो गयी है। अर्शदीप ट्रेड डील में हार्दिक पांड्या के पंजाब में जाने से बदले में मुम्बई इंडियंस को मिले हैं। इस ट्रेड डील के बाद से क्रिकेट जगत में हलचल मची हुई है। इसी को लेकर पठान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पठान का मानना है कि अर्शदीप के आने से मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का और भी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मुम्बई को मिलेगा, साथ ही टीम के विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

इरफान पठान का मानना है कि अर्शदीप के आने से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में जबरदस्त गहराई आयी है। साथ ही कहा कि टीम के पास अब बुमराह के अलावा दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाज हो गये हैं। ये सभी गेंदबाज पावरप्ले में विरोधी बल्लेबाजों को दबाव में डालने की क्षमता भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त टीम के पास बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अश्वनी कुमार का विकल्प भी उपलब्ध है, जिन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए अपने 10 मुकाबलों में 17 विकेट हासिल किए हैं, जिससे शुरुआती ओवरों में कप्तान के पास कई विकल्प होंगे। वहीं डेथ ओवरों की बात करें तो, मुंबई इंडियंस के लिए अर्शदीप और बुमराह मिलकर विरोधी बल्लेबाजी को धवस्त कर सकते हैं। ये दोनों ही गेंदबाज दबाव की परिस्थितियों में शानदार गेंदबाजी करने और महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में मुंबई के पास पारी के दो अहम चरणोंङ्क पावरप्ले और डेथ ओवर में विकेट लेने वाले कई मजबूत विकल्प होंगे। यह कप्तान को गेंदबाजी में रणनीति बनाने की अधिक आजादी देने के साथ ही प्रयोगों में लचीलापन रखने की अनुमति देंगे। कुल मिलाकर, देखा जाये तो अर्शदीप के आने के बाद मुंबई टीम का गेंदबाजी संयोजन काफी मजबूत नजर आ रहा है, जो आईपीएल 2027 में विपक्षी टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में जाने और अर्शदीप के मुंबई में आने से दोनों टीमों की किस्मत पर क्या असर पड़ता है।

आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ के सामने अलग पहचान बनाने की दोहरी चुनौती

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट के दो महान दिग्गजों, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़, जिन्होंने अपने खेल से अनगिनत प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाई, अब उनके बेटों - आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ ने भी क्रिकेट के मैदान पर कदम रखा है। इन युवा खिलाड़ियों के सामने अपने पिता की अविश्वसनीय विरासत को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने की दोहरी चुनौती है, जिसने क्रिकेट जगत में उत्सुकता पैदा कर दी है।

हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में आर्यवीर सहवाग ने यूएई के खिलाफ एक शानदार शतकीय पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने 168 गेंदों पर 160 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 7 छक्के शामिल थे, जो उनकी आक्रामक शैली और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को दर्शाता है। वे नियमित रूप से क्रिकेट अकादमी में अभ्यास करते हैं और उनके पिता वीरेंद्र सहवाग स्वयं भी उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वीरेंद्र सहवाग चाहते थे कि आर्यवीर क्रिकेट के बजाय फुटबॉल खेलें, लेकिन बेटे का रुझान आखिरकार क्रिकेट की ओर रहा। आर्यवीर का मानना है कि वे हर गेंद पर छक्का मारने की बजाय, पहले विकेट पर टिकने और फिर एक बड़ी पारी खेलने पर ध्यान





केंद्रित करते हैं। उन्हें अपने सरनेम सहवाग पर गर्व है और यह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है।

वहीं, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी अपनी क्रिकेट प्रतिभा को निखारने में लगे हैं। उन्होंने एशियन यूथ गेम्स में श्रीलंका के खिलाफ 67 गेंदों पर 87 रनों की प्रभावी पारी खेली थी। अन्वय कर्नाटक की अंडर-14 और अंडर-16 टीमों के लिए भी खेल चुके हैं और नियमित रूप से विकेटकीपिंग का अभ्यास करते हैं, जो उनके पिता राहुल द्रविड़ की तरह बहुमुखी प्रतिभा का संकेत है, जिन्होंने 2003 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली थी। अन्वय को बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियां समझने में अपने पिता से मूल्यवान मार्गदर्शन मिलता है। हालांकि, यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही के मैचों में वे लंबी पारी नहीं खेल सके, लेकिन क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी युवा खिलाड़ी का भविष्य कुछेक मैचों के प्रदर्शन से नहीं आँका जा सकता।

भारतीय क्रिकेट को इन दोनों युवाओं से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि केवल किसी महान खिलाड़ी का बेटा होना सफलता की गारंटी नहीं होता। इसके लिए निरंतर कड़ी मेहनत, अनुशासन, ठोस तकनीक, अच्छी फिटनेस और मानसिक मजबूती अनिवार्य है। एक तरफ आर्यवीर में सहवाग जैसी आक्रामक बल्लेबाजी की झलक देखने की उम्मीद की जा रही है, तो दूसरी तरफ अन्वय में राहुल द्रविड़ की तरह तकनीकी रूप से मजबूत और धैर्यवान क्रिकेटर बनने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अभी इनके करियर की शुरुआत है, और इन्हें अनावश्यक दबाव के बिना आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी विशिष्ट प्रतिभा से भारतीय क्रिकेट में एक अलग और यादगार मुकाम हासिल कर सकें।

मुंबई इंडियंस, नये कप्तान का चयन सोच समझकर समय आने पर करेगी

मुम्बई (यशभारत)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 से ठीक पहले कप्तान हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में जाने से अब मुंबई इंडियंस को नये कप्तान की घोषणा करनी है। इसी को लेकर फ्रैंचाइजी प्रबंधन का कहना है कि सोच विचार के बाद ही सही समय पर नये कप्तान की घोषणा कर दी जाएगी। इस घोषणा के बाद से ही पांच बार टीम को खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा की कप्तानी में वापसी की चर्चाऐं शुरु हो गयी हैं। रोहित के अलावा सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और युवा तिलक वर्मा भी कप्तान के दावेदार माने जा रहे हैं।



मुंबई इंडियंस ने कहा है कि आगामी सत्र को देखते हुए फ्रेंचाइजी अपने कप्तानी विकल्पों का आंकलन सोच-समझकर करेगी। टीम की कप्तानी को लेकर घोषणा समय आने पर ही की जाएगी। यह बयान दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट किसी भी जल्दबाजी में नहीं है और वे टीम के भविष्य के नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प तलाश रहे हैं। फ्रेंचाइजी के लिए यह फैसला आगामी रिटेंशन डेडलाइन और मिनी ऑक्शन की रणनीति के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है, जबकि 16 दिसंबर को गोवा में मिनी ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में, मुंबई इंडियंस को अपनी टीम का संयोजन और उसके नेतृत्व दोनों को इन महत्वपूर्ण तिथियों से पहले तय करना होगा। हार्दिक का मुंबई इंडियंस के साथ एक लंबा और सफल सफर समाप्त हो गया है। उन्होंने 2015 में मुंबई के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी और एक युवा खिलाड़ी से दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में उभरे थे। उन्होंने मुंबई को चार आईपीएल खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।ट्रेड डील के तहत, हार्दिक पांड्या अब पंजाब किंग्स में चले गये हैं। अब सभी की निगाहें मुंबई इंडियंस की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं कि आईपीएल 2027 में कौन सा खिलाड़ी पांच बार की चैंपियन टीम का नेतृत्व करेगा। यह एक ऐसा निर्णय है जो टीम के आगामी प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालेगा।

अगले माह होंगे भारतीय ओलंपिक संघ चुनाव, 30 महासंघ करेंगे मतदान

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की कार्यकारी परिषद के बहुप्रतीक्षित चुनाव 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें देश के 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के प्रतिनिधि नए नेतृत्व का चुनाव करेंगे। हालांकि, इस चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई), भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) और इंडियन गोल्फ यूनियन (आईजीयू) जैसे कुछ महत्वपूर्ण खेल महासंघों को अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण मतदान से बाहर कर दिया गया है। , जिससे आगामी चुनावों में कुछ बड़े खेलों की अनुपस्थिति स्पष्ट हो गई है।

कुल 71 मतदाता आईओए के अगले शीर्ष अधिकारियों का चुनाव करेंगे। इसमें मुक्केबाजी महासंघ को उसकी गहरी आंतरिक गुटबाजी के चलते बाहर रखा गया है, जो भारतीय मुक्केबाजी के लिए एक चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। इसी प्रकार, तदर्थ समिति द्वारा संचालित टीटीएफआई को भी मतदान का अधिकार नहीं मिला है। इंडियन गोल्फ यूनियन (आईजीयू) के मामले में बाधा यह है कि इसके एक गुट को आईओए और दूसरे को खेल मंत्रालय ने मान्यता दे रखी है, जिसके परिणामस्वरूप उसे भी निर्वाचक मंडल से बाहर रखा गया है। यह उन महासंघों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जिन्हें अपनी आंतरिक संरचनाओं को ठीक करने की आवश्यकता है ताकि वे भारतीय ओलंपिक परिवार का सक्रिय हिस्सा बने रह सकें।

निर्वाचक मंडल में शामिल 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों को पांच दिसंबर के चुनाव के लिए एक पुरुष और एक महिला प्रतिनिधि नामित करना होगा।

रंग संसार

गुजरात बोर्ड की टॉपर पायल ने की है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई



मुंबई (यशभारत)। बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी अपने बेबाक अंदाज और निजी जिंदगी से जुड़े खुलासों के कारण अक्सर चर्चा में रहती हैं। पायल ने फिल्मों से लेकर रियलिटी शोज तक अपनी अलग पहचान बनाई है। बड़े पर्दे पर अभिनय करने के साथ-साथ उन्होंने छोटे पर्दे के कई लोकप्रिय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। बिग बॉस से लेकर लॉकअप तक उनका सफर दर्शकों के बीच खासा चर्चित रहा है। पायल रोहतगी का जन्म 9 नवंबर 1980 को हैदराबाद में हुआ था। पढ़ाई में अच्छी रहने वाली पायल ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह गुजरात बोर्ड की टॉपर भी रह चुकी हैं। हालांकि, पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका रुझान अभिनय और मॉडलिंग की ओर बढ़ने लगा। साल 2000 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई विज्ञापनों में काम किया। धीरे-धीरे उन्हें फिल्मों में भी अवसर मिलने लगे। पायल ने साल 2002 में फिल्म ये क्या हो रहा है से बॉलीवुड में शुरुआत की। इसके बाद वह तुमसे मिलकर, प्लान, पुलिस फोर्स-एन इनसाइड स्टोरी, रक्त, तौबा तौबा, लैला-ए-मिस्ट्री और चेतना-द एक्साइटमेंट जैसी फिल्मों में नजर आई। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 36 चाइना टाउन में उन्होंने ग्रेसी का किरदार निभाया था। इसी साल वह फिल्म कॉरपोरेट में भी दिखाई दीं।

इसके अलावा ढोल, हे बेबी, अपना सपना मनी मनी, उगली और पगली, दिल कबड्डी और वैलेंटाइंस नाइट जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। फिल्मों के साथ पायल ने टेलीविजन पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। साल 2008 में वह बिग बॉस 2 में शामिल हुईं। शो में उनके बेबाक व्यवहार ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इसके बाद उन्होंने राज पिछले जन्म का, जोर का झटका, सर्वाइवर इंडिया, नच बलिए 7 और बिग बॉस 7 जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। धारावाहिकों में भी उन्होंने काम किया, जिनमें हमने ली है शपथ, हमसफर्स, एजेंट राघव और सूर्यपुत्र कर्ण शामिल हैं। साल 2022 में पायल कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में नजर आईं। यहां उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई निजी किस्से साझा किए और अपने खेल से दर्शकों का ध्यान खींचा। वह शो की पहली रनरअप रहीं। पायल की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही है।

ओट्टनथुल्लल देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए: सोना महापात्रा

मुंबई (यशभारत)। हाल ही में प्रसिद्ध गायिका सोना मोहपात्रा ने केरल में दीपावली का पावन पर्व मनाया। इस दौरान वे पारंपरिक कला रूप ओट्टनथुल्लल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। सोना मोहपात्रा ने इस अनूठी कला के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने अनुभव साझा किए। सोना मोहपात्रा ने अपनी केरल यात्रा और इस शानदार प्रदर्शन को देखने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। उन्होंने इसे संगीत, थिएटर, नृत्य, कविता, कॉमेडी और कहानी कहने का एक अद्भुत संगम बताया। गायिका ने अपने अनुभव में लिखा, केरल में हमारी शानदार दीपावली की छुट्टियों की एक छोटी-सी झलक। परिवार, त्योहार, खाना, बैकवाटर और भी बहुत कुछ, लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा हाईलाइट ओट्टनथुल्लल का यह असाधारण प्रदर्शन है। दो कलाकार, एक मृदंगम, संगीत, थिएटर, नृत्य, कविता, कॉमेडी और कहानी कहने की पूरी दुनिया। इसे देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई और आखिर में मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन में द्रौपदी द्वारा भीम को खुशबूदार कल्याण सौगंधिकम फूल की खोज में भेजने की कहानी को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया कि वे पूरी तरह से उसमें खो गईं। गायिका ने कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे मुख्य कलाकार पलक झपकते ही एक किरदार से दूसरे किरदार में बदल रहे थे, केरल की लोक और शास्त्रीय संगीत परंपराओं से लिए गए बेहद मुश्किल गीतों को गा रहे थे, और अद्भुत शारीरिक ऊर्जा के साथ नृत्य कर रहे थे। उनके भाव, आवाज़, मूड और व्यक्तित्व को हैरान कर देने वाली आसानी से बदलने की क्षमता ने सबको चौंका दिया। एक गायिका के तौर पर, सोना इस सांस पर नियंत्रण और कलात्मक महारत को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने मृदंगम वादक को वन-मैन ऑर्केस्ट्रा बताया, जो नाटकीय प्रभावों, लयबद्ध बातचीत, ठहराव और संगीत की शरारतों से भरा पूरा साउंडस्केप बना रहे थे, साथ ही कोरस की भूमिका भी निभा रहे थे। सोना ने बताया कि कैसे सिर्फ दो लोगों ने अपनी कला की महारत से पूरे दर्शकों को बांधे रखा। इस प्रदर्शन में कॉमेडी का भी एक अनूठा पहलू था ङ्क तेज, सहज और बेहद समझदारी भरी। कलाकार दर्शकों में से अनजान लोगों को चुनकर सबको कहानी में शामिल करते थे, और बिना किसी सस्ते अपमान के सबको हंसाते थे। सोना ने यह भी बताया कि यह कला सिर्फ मंदिर, ऑडिटोरियम या हेरिटेज फेस्टिवल तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक लिविंग रूम, शादी, कॉर्पोरेट कार्यक्रम, गांव के चौक या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच को भी रोशन कर सकती है।





गुरमीत के लिए भावनाओं और लंबे जुड़ाव का सफर है मिर्जापुर

मुंबई (यशभारत)। निर्देशक गुरमीत सिंह के लिए वेब सीरीज मिर्जापुर केवल एक सफल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भावनाओं और लंबे जुड़ाव का सफर है। गुरमीत सिंह का मानना है कि किसी भी फिल्म या सीरीज को बनाते समय सबसे जरूरी काम लेखक की मूल भावना को समझना और उसे पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारना है।

गुरमीत सिंह के मुताबिक, स्क्रिप्ट पढ़ते समय जो रोमांच और उत्साह महसूस होता है, वही अनुभव दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। गुरमीत सिंह ने मिर्जापुर फ्रेंचाइजी और इससे जुड़ी फिल्म के रचनात्मक पक्ष पर बात करते हुए बताया कि इसकी कहानी निर्देशक के सामने काम करने के लिए काफी सामग्री और चुनौतियां रखती है। ऐसे में उनका ध्यान दूसरी छोटी-छोटी बातों के बजाय कहानी की मूल भावना पर रहता है। उनके अनुसार, जब स्क्रिप्ट मजबूत होती है और उसमें दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता होती है, तो निर्देशक का मुख्य काम उसे सही तरीके से पर्दे पर प्रस्तुत करना होता है। उन्होंने बताया कि किसी भी कहानी को फिल्माने से पहले यह समझना जरूरी है कि लेखक ने कागज पर क्या लिखा है और उस विचार को दर्शकों के सामने किस रूप में पेश किया जा सकता है। वह चाहते थे कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय उन्हें और उनकी टीम को जो उत्साह महसूस हुआ, वही उत्साह दर्शकों को भी देखने को मिले। उनके लिए निर्देशन का असली उद्देश्य कहानी के जादू को बिना अनावश्यक बदलाव के जीवंत करना है। गुरमीत सिंह ने यह भी

रहमान की संगीत प्रतिभा की घई ने की जमकर तारीफ

मुंबई (यशभारत)। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई ने संगीतकार ए. आर. रहमान के भारतीय संगीत उद्योग में अतुलनीय योगदान किया और उन्हें संगीत का वरदान बताया है। सोशल मीडिया पर घई ने रहमान के साथ एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने रहमान की असाधारण संगीत प्रतिभा और किसी भी संस्कृति या शैली के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता की खूब सराहना की।

रहमान को घई ने हमारे ब्रह्मांड से मिली एक वरदान जैसी प्रतिभा कहकर संबोधित किया। इस दौरान सुभाष घई ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ताल के लिए रहमान से संपर्क करने का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार 1999 की इस फिल्म के लिए रहमान को संगीत का प्रस्ताव दिया तो वे काफी घबराए हुए थे। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें यह आशंका थी कि रहमान शायद हिंदी फिल्मों के संगीत से उतना वाकिफ न हों या हिंदी गानों



के लिए वे कितने सहज होंगे। हालांकि, उनकी चिंता तब थोड़ी दूर हुई जब रहमान ने उन्हें बताया कि उन्होंने कभी उनकी ही फिल्म हीरो के लिए बांसुरी बजाई थी। इस जानकारी से घई को राहत मिली और उन्हें विश्वास हो गया कि रहमान भारतीय संगीत की बारीकियों से अच्छी तरह परिचित हैं। सुभाष घई ने इस बात पर जोर दिया कि ए. आर. रहमान ने लगान, रंग दे बसंती और रॉकस्टार जैसी फिल्मों के माध्यम से बॉलीवुड की संगीत संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी अद्वितीय संगीत रचनाओं ने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी और श्रोताओं को एक बिल्कुल नया अनुभव प्रदान किया।

उन्होंने यह भी बताया कि रहमान ने अपने हिंदी गाने जय हो के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार भी जीता, जिससे भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान मिली। घई के अनुसार, ए. आर. रहमान में किसी भी देश और किसी भी संस्कृति की किसी भी आवाज़ को सीखकर उसे संगीत में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। वे हर तरह की फिल्म और हर जगह के हर निर्देशक के साथ सफलतापूर्वक काम करते हैं।

मुख्यमंत्री ने महती पत्रकार वार्ता में विश्वास व्यक्त किया

जनजातीय समाज 2047 के विकसित भारत का बनेगा मजबूत आधार

यश भारत



रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है। श्री साय ने भगवान बिरसा मुण्डा को नमन करते हुए कहा है कि 15 नवम्बर 1875 को वर्तमान झारखण्ड प्रदेश के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे युवा बिरसा ने अंग्रेजी शासन द्वारा जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीने जाने के विरुद्ध समाज को नशे व कुरीतियों से दूर रहकर अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता से लड़ने के लिए जागृत किया। उन्होंने 'उलगुलान' (महाक्रांति) का नेतृत्व करते हुए 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' (हमारा देश, हमारा राज) का अमर नारा दिया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया, किंतु उनके संघर्ष की बदौलत 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की। इसी कारण समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है।

मुख्यमंत्री साय गुरुवार को यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवम्बर 2026 तक मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव सप्ताह' के अंतर्गत आहूत महती पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री साय ने भगवान बिरसा मुण्डा के जीवन संघर्ष, स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायकों के बलिदान, मोदी सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं, विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और 'विकसित भारत 2047' के विज़न को विस्तार से मीडिया के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री साय ने 2021 से शुरू हुई 'जनजातीय गौरव दिवस' की यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 नवम्बर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया। भोपाल में पहला आयोजन हुआ, राँची में बिरसा मुण्डा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। सन् 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुँचीं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक 'पीएम जनमन' अभियान का शुभारंभ किया। 2024 में जमुई (बिहार) में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाया गया। 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएँ समर्पित की गईं। वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि देते हैं। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक (कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत) जनजातीय नागरिक हैं। देश में 720 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं, और 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री साय ने भाजपा की प्रतिबद्धता गिनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न'अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में छत्तीसगढ़ व झारखण्ड का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया। मोदी सरकार में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ (विष्णुदेव साय), ओड़िशा (मोहन चरण माँझी) और अरुणाचल प्रदेश (श्री पेमा खाण्डू) में भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें स्ज़ के लिए आरक्षित हुईं। राजनीतिक विश्वास का प्रमाण देते हुए श्री साय ने बताया कि लोकसभा की 47 अजजा सीटों में से 26 पर तथा विधानसभाओं की 568 अजजा सीटों में से 209 पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भी सभी 16 आरक्षित सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है।

1857 से एक सदी पूर्व ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दिया था स्वाधीनता संग्राम

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही जनजातीय वीरों ने प्रारम्भ कर दी थी। देश के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए श्री साय ने कहा कि सन् 1784 में तिलका मांझी और 1855 में सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव तथा फूलो-झानो, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखण्ड में तेलंगा खड़िया व बुधु भगत, निमाड़-मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू जनजातीय समाज के महानायक हैं। श्री साय ने कहा कि 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियाँवाला बाग से भी पहले का है, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ जाकर नमन किया। श्री साय ने कहा कि दशकों तक इतिहास को चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और इन हजारों सेनानियों को पाठ्यपुस्तकों से भी गायब रखा गया।

स्वच्छता पुरस्कार लेकर लौटे साव और निकायों के प्रमुखों का जोरदार स्वागत

राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सम्मान स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे निरंतर सुधार, प्रतिबद्धता और प्रभावी प्रयासों का प्रमाण : अरुण साव



सैकड़ों स्वच्छता दीदियां और अधिकारी-कर्मचारी अभिनंदन के लिए जुटे

यश भारत

रायपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रायपुर लौटे उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव और रायपुर, बिलासपुर एवं बिल्हा के निर्वाचित प्रमुखों का विमानतल पर जोरदार स्वागत किया गया। तीनों निकायों से सैकड़ों की संख्या में स्वच्छता दीदियां एवं अधिकारी-कर्मचारी उप मुख्यमंत्री साव और अपने निकाय प्रमुखों रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी तथा बिल्हा नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वन्दना जेंड्रे के स्वागत व अभिनन्दन के लिए विमानतल पहुंचे थे। पारंपरिक लोक नृत्यों और गाजे-बाजे के साथ पुरस्कार ग्रहण करने नई दिल्ली गए प्रतिनिधि मंडल का रायपुर लौटने पर शानदार अभिनन्दन किया गया।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर लौटने पर लगातार दूसरे वर्ष इन तीनों शहरों की उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने लगातार दूसरे वर्ष अपनी राष्ट्रीय पहचान कायम रखी है। लगातार दो वर्षों तक तीन-तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे निरंतर सुधार, प्रतिबद्धता और प्रभावी प्रयासों का प्रमाण है। इस उपलब्धि के पीछे सफाई मित्रों का अथक परिश्रम, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। उन्होंने सफाई मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रतिदिन शहरों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि शहरी स्वच्छता को मजबूत बनाने में हमारी 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियों का योगदान अहम है। घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे के पृथक्करण और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में उनकी सक्रिय भूमिका है। राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान स्वच्छता दीदियों के योगदान का भी सम्मान है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल कुछ शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ एवं सुविधापूर्ण बनाना है। बिलासपुर, रायपुर और बिल्हा की यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों को भी प्रेरित करेगी।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन की सरकार में बिल्हा, बिलासपुर और रायपुर ने इस वर्ष भी स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बरकरार रखी है। पिछली बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में भी बिल्हा अपनी श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर था। वहीं बिलासपुर ने तीन लाख से दस लाख की आबादी वाले शहरों में द्वितीय स्थान हासिल किया था।

बिलासपुर ने इसे बरकरार रखते हुए इस बार देश के सबसे स्वच्छ रीवर फ्रंट वाले शहरों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राजधानी रायपुर को छत्तीसगढ़ का 'प्रॉमिसिंग (क्षमतावान) स्वच्छ शहर' का पुरस्कार मिला था। इस बार रायपुर को राज्य के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर शहर में तैयारियां शुरू

रायपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। खासतौर पर महिलाएं छठ पूजा की तैयारियों में जुट गई हैं। कोई पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री खरीद रहा है तो कोई साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और अन्य शृंगार का सामान पसंद कर रहा है। उधर तालाबों व नदी के घाट पर आयोजन समिति व निगम प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थागत तैयारियां की जा रही है।

बाजार में महिलाओं की भीड़ नजर आने लगी है। छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाएं परंपरा के अनुसार सोलह शृंगार कर छठी मैया की पूजा-अर्चना करेंगी। इसके लिए कपड़ों और आभूषणों की दुकानों पर भी खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया है।

छठ पर्व केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार की खुशहाली, संतान की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना से जुड़ा आस्था का पर्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। नहाय-खाय से इसकी शुरुआत होती है।

इसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है। व्रती महिलाएं पूरी श्रद्धा और नियम-संयम के साथ पूजा की तैयारियां करती हैं। बाजार में पूजा के लिए बांस की टोकरी, सूप, दौरा,



नारियल, केला, गन्ना, मौसमी फल, ठेकुआ बनाने की सामग्री और मिट्टी के दीपक की मांग बढ़ रही है।

छठ पूजा में प्रसाद के रूप में ठेकुआ का विशेष महत्व होता है। इसे घर में शुद्धता और पारंपरिक विधि से तैयार किया जाता है। महिलाएं पूजा में चढ़ाए जाने वाले फल और अन्य सामग्री की सूची बनाकर खरीदारी कर रही हैं, ताकि पर्व के दौरान किसी चीज की कमी न रहे।

छठ पर्व पर पारंपरिक परिधान और सोलह शृंगार का विशेष महत्व है। महिलाएं इस अवसर पर लाल, पीली, हरी और अन्य शुभ रंगों की साड़ियां खरीद रही हैं। इसके साथ ही चूड़ियां, बिछिया, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, काजल और मेहंदी जैसी शृंगार सामग्री की भी खरीदारी की जा रही है।

रायपुर जिले में पटवारियों पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 7 निलंबित

जिले के विभिन्न अनुविभागों एवं तहसीलों में 229 पटवारियों को नोटिस जारी, कार्य पर वापस लौटने के निर्देश

यश भारत

रायपुर। रायपुर जिले में कार्य पर वापस नहीं लौटने वाले पटवारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिले के विभिन्न अनुविभागों एवं तहसीलों में अब तक 7 पटवारियों को निलंबित किया गया है, वहीं 226 पटवारियों को कार्य पर वापस लौटने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायपुर तहसील में एक पटवारी को निलंबित किया गया है, जबकि 51 पटवारियों को कार्य पर वापस लौटने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसी प्रकार धरसींवा तहसील में 30 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। तिल्दा अनुविभाग में एक पटवारी को निलंबित किया गया है तथा 48 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं आरंग अनुविभाग में 2 पटवारियों को निलंबित करने के साथ ही 57 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अभनपुर अनुविभाग में भी जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए 3 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इनमें तहसील गोबरा नवापारा का एक तथा अभनपुर तहसील के दो पटवारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गोबरा नवापारा तहसील में 19 और अभनपुर तहसील में 24 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस प्रकार अभनपुर अनुविभाग में कुल 43 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पटवारियों को कार्य पर वापस लौटकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।

अदान सहायता के नाम पर किसानों को ठगने की कोशिश कर रही सरकार- कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अदान सहायता के नाम पर सरकार किसानों को ठगने की कोशिश कर रही है प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार किसानों को 3100 रू में 2441 रू समर्थन मूल्य घटाकर प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल अदान सहायता 13839 राशि की गणना कर रही है। जबकि धान की कीमत 3100 में 3 वर्षों में बढ़ा समर्थन मूल्य 258 से जोड़कर 3358 में वर्तमान समर्थन मूल्य (3358-2441) को घटाकर 917 रू प्रति क्विंटल एकड़ गुना 21 कुंटल 19257 प्रति कुंटल के हिसाब से अदान सहायता राशि दी जानी चाहियें इस हिसाब से सरकार प्रति एकड़ किसानों को 5418 रू प्रति एकड़ कम देने जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने 2500 कीमत देती थी लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर 2640 और 2660 रू के हिसाब से कीमत दिया था।



प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार अदान सहायता राशि को अलग से क्यो देने जा रही है भाजपा ने तो चुनाव में एकमुश्त 3100 रू के हिसाब से धान की कीमत का भुगतान करने का वादा किया धान की कीमत का भुगतान करने का वादा किया था अब बढ़ा समर्थन मूल्य के हिसाब से सरकार किसानों को 3358 प्रति कुंटल के हिसाब से भुगतान करे। मोदी की गारंटी के प्रत्येक ग्राम पंचायत मे नगद भुगतान केन्द्र खोले।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है वह पूरा धान खरीदना नही चाहती केवल अदान सहायता राशि देकर किसानों को अपना धापन औने पौने दाम में बेचने को मजबूर करना चाह रही है। सरकार इस बात की गारंटी ले कि किसानों से पूरा प्रति एकड़ 21 कुंटल के हिसाब से धान खरीदा जायेगा। केवल 659 रू देकर 2441 प्रति क्विंटल की देने से बच रही है सरकार।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार रकबा कटौती करने तथा रकबा समर्पण और गिरदावरी तथा भौतिक सत्यापन के नाम पर किसानों से पूरा धान नही खरीदेगी किसानों को केवल अदान सहायता राशि वह थी आधा अधूरे रकबे पर देने की तैयारी की जा रही है। किसानों को उनकी पूरी उपज 21 कुंटल प्रति एकड़ की 3358 रू के हिसाब से भुगतान चाहिये। अनावरी रिपोर्ट गिरादवली और एकल समर्पण की पर परदेदारी करने किसानों को 659 रू का लालच दे रही है सरकार लक्ष्य में कटौती करने कम धान खरीदने और किसानों में कोचियों बिचौलियों के शोषण का शिकार बनाने के लिये यह कुचक्र रचा गया है ताकि कम से कम धान खरीद सके।

लारा में 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ

यश भारत

रायपुर। रायगढ़ जिले के लारा में छत्तीसगढ़ स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया।

प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री चौधरी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करें और अपने प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को आगे बढने और अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान करेंगी।



पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के अवैध विक्रय व पंजीकरण के संबंध में सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेजा गया

अनुमानित 500 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति की जांच प्रक्रियाधीन, कांग्रेस कर रही दुष्प्रचार - डॉ.सलीम राज

यश भारत

रायपुर। प्रदेश की ऐसी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां जिनके सम्बंध में अवैध विक्रय व अवैध पंजीकरण की शिकायत/जानकारी प्राप्त हुई है जिसका अनुमानित मूल्य 500 करोड़ रूपये है, उक्त पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के सम्बंध में छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा निरंतर कार्यवाही किया जाकर सम्बंधित जिला कलेक्टर व जिला पंजीयक को पत्र जारी कर वक्फ सम्पत्तियों के अवैध विक्रय व अवैध पंजीयन को शून्य किये जाने एवं वक्फ सम्पत्ति को वापस लाने हेतु प्रेषित किया गया है साथ ही सम्बंधितों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के



सम्बंध में भी निरंतर पत्र जारी किये गये है।

इस संदर्भ में प्रसारित समाचार जिसमें यह कहा जा रहा है कि डॉ.सलीम राज के दावे झूठे हैं इसका खंडन यह है कि कार्यालय छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जो सूचना का अधिकार के तहत जानकारी दी गई थी वह अध्यक्ष की जानकारी के बिना दी गई और भ्रामक जानकारी दी गई जिसके कारण सम्बंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

प्रदेश की ऐसी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां जिनका अवैध क्रय-विक्रय व अवैध पंजीकरण हुआ है उसकी सी.बी.आई. जांच कराये जाने हेतु माह मई 2026 को गृह मंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन, गृह मंत्री, छ.ग.शासन के साथ सी.बी.आई. को पत्र जारी कर निवेदन किया गया है इसके साथ ही पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के अवैध क्रय-विक्रय व अवैध पंजीकरण को शून्य कराया जाकर वक्फ सम्पत्ति को वापस लाने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में सम्बंधित जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक को भी कार्यालय द्वारा पत्र जारी किये गये हैं जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार से यह कहा जाना कि छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड के दावे झूठे हैं यह बात बेबुनियाद और कांग्रेस की दूषित मानसिकता को परिलक्षित करता है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में वक्फ सम्पत्तियों पर से कितने अतिक्रमण को हटाया गया? कितनी वक्फ सम्पत्तियों को सुरक्षित कर समाज कल्याण के लिए उपयोग में लाया गया? कांग्रेस केवल अपने कुकृत्यों को छुपाने और अपनी निष्क्रीयता को छुपाने के लिए इस प्रकार से गलत प्रचार करती रहती है। कांग्रेस केवल हल्ला मचाने का कार्य करती है और भाजपा समाज कल्याण में काम करने पर विश्वास करती है। कांग्रेस के तथाकथित लोग जो वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं उन्हें कांग्रेस संरक्षण और समर्थन देने का कार्य करती रही है इसलिए इस प्रकार की बयानबाजीयां करती है।

स्वामी प्रकाशक मुद्रक आशीष कुमार शुक्ला , मिशन मीडिया (प्रा.लि.) प्लाट नम्बर -9/1 छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्प्लेक्स,रजबंधा मैदान, रायपुर छत्तीसगढ़ -492001 से मुद्रित एवं हॉउस नम्बर 18/303 सेक्टर 27 ,नवा रायपुर ,रायपुर छत्तीसगढ़ -492018 से प्रकाशित। संपाादक आशीष कुमाार शुक्लाा सलाहकार संपाादक श्याम कटारे
प्रबंध संपादक अजय क्षत्रे, स्थानीय संपादक अरविंद कुमाार पांडेय मो .-9827117441 RNI-CTHI/26/A5 206 ईमेल -raipuryashbharat@gmail.com (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) , सिटी ऑफिस- आर्यन टॉवर द्वितीय तल द्रोणाचार्य स्कूल के पास रायपुर, मो .-9111201000 (न्यायालय क्षेत्र अधिकार रायपुर)